

नई दिल्ली
शनिवार
10 अक्टूबर 2026
वर्ष: 13, अंक: 37
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु0
E-mail story@sadbhawna.today sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ को तेजी...**पेज-05**

DELHIN/2014/58158

आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में तन मन से जुटे...**पेज-08**

एक नजर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12.95 अरब डॉलर घटकर 734.61 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे हप्ते गिरावट दर्ज हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार दो अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में 12.95 अरब डॉलर घटकर 734.61 अरब डॉलर रहा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 25 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 18.34 अरब डॉलर घटकर 747.56 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि दो अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 10.66 अरब डॉलर घटकर 604.75 अरब डॉलर रही। इस दौरान स्वर्ण भंडार का भी मूल्य 2.29 अरब डॉलर घटकर 106.41 अरब डॉलर रहा। विशेष आह्वान अधिकार (एसडीआर) 15 लाख डॉलर बढ़कर 18.66 अरब डॉलर हो गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित जमा 1.5 करोड़ डॉलर घटकर 4.79 अरब डॉलर रहा। उल्लेखनीय है कि चार सितंबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर के रिकॉर्ड 785.71 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।

गुजरात के कच्छ में ट्रक और बोलेरो के बीच टक्कर में सात मजदूरों की मौत

भुज/अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ में आज सुबह ट्रक और बोलेरो के बीच टक्कर में सात मजदूरों की मौत हो गई। बोलेरो गाड़ी में 15 से ज्यादा मजदूर सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि केबिन में फंसे लोग दर्द से कराह रहे थे। वहां आसपास मौजूद लोग यह मंजर देख आवाक थे। कच्छ जिले में आज मजदूरों को ले जा रही एक बोलेरो गाड़ी खावड़ा के पास आईए पार्क के रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में सात मजदूरों की मौत हो गई। बोलेरो में 15 से ज्यादा मजदूर सवार थे, जहाँकि कुछ घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफ़रा-तफ़री मच गई। अभी घायलों की संख्या और उनकी हालत के बारे में अभी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हादसे के बाद उन्हें खावड़ा से भुज ले जाया गया। उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस हादसे से पूरे इलाके में मातम छ गया।

उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी इमैनुएल की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी त्यागी इमैनुएल सेक्टरनार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने एएस पर लिखा, ‘ मैं त्यागी इमैनुएल के बलिदान तथा समाज में उनके योगदान का सम्मान करता हूं। उन्होंने सामाजिक न्याय, समाजता और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए जिस साहस के साथ संघर्ष किया, वह सराहनीय है। कम उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद, उन्होंने देश की आजादी के बाद जातिगत भेदभाव के खिलाफ़ अथक प्रयास किए और लोगों के अधिकारों व आत्म-सम्मान को स्थापित करने के लिए काम किया। उन्होंने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने, युवाओं को एकजुट करने और शिक्षा तथा अधिकारों के प्रति चेतना जगाने में अहम भूमिका निभाई। समाजता, सामाजिक न्याय, भाईचारे और सद्भाव वाले समाज के निर्माण के उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करते रहे।

नितिन नवीन ने काशी क्षेत्र की 71 विधानसभा सीटों और एमएलसी चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दिया मंत्र

वाराणसी,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने काशी क्षेत्र की सभी 71 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया।

उन्होंने आगामी स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों में प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए तत्काल चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सात और आठ अक्टूबर को काशी प्रवास के दौरान आयोजित सात संगठनात्मक बैठकों गुरुवार शाम संक्षेप हुईं। इन बैठकों में जिला, क्षेत्र एवं प्रवेश स्तर के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ पूर्व पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना रुडे

आवाज़ अधिकार की



राष्ट्रपति से मिला इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल, मुर्मु ने वोट चोरी के आरोपों पर मांगे सबूत: राहुल

नई दिल्ली,एजेंसी। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और वोट चोरी के आरोपों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति को पिछले चार दिनों से वोट चोरी के खिलाफ चलाये जा रहे आंदोलन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उनसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग भी की गयी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी के मामलों के सबूत मांगे हैं, जिन्हें विपक्ष संकलित कर उन्हें सौंपेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल की बातें ध्यान से सुनीं और मामले की जांच करने तथा उचित कदम उठाने पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी के आरोपों को खारिज नहीं किया, बल्कि इस संबंध में सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट चोरी के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश दोषी हैं और वे मिलकर लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रपति के सामने सभी सबूत रखने के लिए तैयार है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव रास्ता अपनायेगा। विपक्षी सांसद पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गये थे लेकिन उन्हें रोककर पुलिस थाने ले जाया गया। इसके बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया गया और अब राष्ट्रपति के सामने मामला रखा गया है। विपक्ष सोमवार को उच्चतम न्यायालय में भी इस मुद्दे को उठायेगा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मामले की जांच करने तथा विवरण देखने की बात कही है। सुश्री बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति ने सबूत मांगे हैं, जिन्हें विपक्ष उन्हें उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा कि देश इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और राष्ट्रपति से संविधान की संरक्षक के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मामले की

उग्र में राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन, भाजपा के आठ और सपा के दो उम्मीदवार निर्वाचित



लखनऊ,एजेंसी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आठ और समाजवादी पार्टी (सपा) के दो उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया गया है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित सीटों के बराबर रहने के कारण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने सभी 10 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। इसके बाद विधानसभा में दो निर्वाचित सांसदों को प्रमाण पत्र सौंपे



जांच का आश्वासन दिया है। प्रतिदिन मंडल के राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले गठबंधन के सांसदों ने विजय चौक तक मार्च निकाला। इससे पहले सांसदों ने संसद भवन के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बैठक की। बैठक में राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाले ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया और विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। इसके बाद सांसद संसद भवन से विजय चौक की ओर रवाना हुए। श्री खरगे ने मार्च में शामिल होने के दौरान कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने खुले तौर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुमार को उनकी गलतियों के बारे में समझाने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद वह नहीं माने। दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद मोदी सरकार श्री कुमार को पद से हटाने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष कई वर्षों से चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी समस्याएं सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने रख रहा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी। आजादी के बाद संविधान ने जनता को वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन अब यह अधिकार छीने जाने का खतरा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार छोटी मछली हैं लेकिन उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के अधिकार छीनकर तानाशाही करना चाहती है। यदि तानाशाही आती है तो लोकतंत्र, संविधान

उपचुनाव में राजग की जीत के बाद बोले मोदी, सरकार के सुशासन के एजेंडे से गहरे से जुड़े हैं लोग: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली जीत पर मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि लोगों का सरकार के सुशासन के एजेंडे से मजबूत जुड़ाव है।

उपचुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद श्री मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘आपके निरंतर आशीर्वाद के लिए प्रज्ञा का आभार! नगांव (असम) के लोकसभा परिक्राम और नंदीग्राम तथा रेजीनगर (पश्चिम बंगाल) के विधानसभा परिणाम एक बार फिर दिखाते हैं कि जनता का भाजपा-एनडीए के सुशासन के एजेंडे से गहरा जुड़ाव है। मैं भाजपा के विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की भी सराहना करता हूं। मैं पुडुचेरी के शट्टनचावडी में जीत के लिए अपने मूल्यवान एनडीए सहयोगी, एआईएनआरसी को भी बधाई देता हूं।

विधानसभा की 5 सीटों के उपचुनाव में राजग तीन पर विजयी, टीवीके एक जीती

नई दिल्ली,एजेंसी। देश के तीन राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में एक लोकसभा तथा पांच विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और क्षेत्रीय दलों को सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीटों पर भाजपा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। तमिलनाडु के धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में तमिलगा वेत्री कडगम (टीवीके) की उम्मीदवार सत्यभामा.पी विजयी हुईं, जबकि मधुरांतकम सीट पर टीवीके के के. मरागथम कुमारवेल मतगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आगे चल रहे हैं। पुडुचेरी के तट्टांचावडी में भाजपा-नीत राजग के घटक दल सत्तारूढ़ एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद ने जीत दर्ज की। वहीं, असम के नगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने 1.66 लाख से अधिक मतों की निर्णायक बढ़त बना रखी है। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार हासिरानी रथ ने 1,22,753 मतों के अंतर से जीत

विधानसभा की 5 सीटों के उपचुनाव में राजग तीन पर विजयी, टीवीके एक जीती



हासिल की। मतगणना के 15 राउंड के बाद आए परिणाम में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। रेजिनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार शाखारव सरकार ने 75,748 मतों से जीत दर्ज की।

नंदीग्राम में हासिरानी रथ की जीत इसलिए भी चर्चा में रही, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पिछले चुनावी जीत के अंतर को पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 81,230 मतों से जीत दर्ज की थी। वर्ष 2021 में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उनकी जीत का



जबकि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी प्रदर्शन के आयोजन के लिए कम से कम 10 दिन पहले पुलिस को सूचना देना आवश्यक है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि सीजेपी को पूर्व में भी प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी लेकिन उस दौरान उसने कानूनी निर्देशों और अपने आश्वासनों का पालन नहीं किया था। सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल ने 57 स्टेशनों पर शुक्रवार रात नौ बजे से ही यात्रियों के प्रवेश और निकासी पर रोक लगा दी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से अनुरोध किया था। यह रोक शनिवार को अगले आदेश तक जारी रहेगी। मेट्रो के अनुसार नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर अन्य सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर मध्य दिल्ली में कर्तव्य पथ और जनपथ चौराहे के चार किलोमीटर के दायरे में शुक्रवार रात दस बजे से शनिवार रात दस बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद करने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, धूल नियंत्रण में लापरवाही पर डीजेबी, एनएचएआई, डीएमआरसी और एनबीसीसी को नोटिस

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्माण स्थलों पर निगरानी तेज कर दी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से सरकारी और निजी परियोजनाओं का नियमित एवं औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान धूल नियंत्रण के निर्धारित उपायों का पालन नहीं पाए जाने पर दिल्ली जल बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली मेट्रो और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) से जुड़ी कुछ परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम सभी सरकारी और निजी एजेंसियों के लिए समान हैं। किसी भी विभाग, निर्माण एजेंसी, ठेकेदार या निजी कंपनी को नियमों के उल्लंघन पर छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है। विकास कार्य जारी रहें, लेकिन पर्यावरणीय मानकों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

डीपीसीसी के निरीक्षण में पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन बिछाने के कार्य में धूल नियंत्रण संबंधी उपायों की जांच की गई। इसके अलावा एनएचएआई के अंतर्गत एनएच-9 और रोहतक रोड पर पंजाबी बाग से टिकरी कलां तक 17.2 किलोमीटर लंबे गलियारे में, विशेषकर मुंडका



मेट्रो स्टेशन और मुंडका औद्योगिक क्षेत्र के आसपास निरीक्षण किया गया। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर कृषि भवन के निकट गेट नंबर-3 के पास दिल्ली मेट्रो एवं सेंट्रल विस्टा परियोजना से संबंधित कार्य तथा सरोजिनी नगर और नेताजी नगर में एनबीसीसी की जीपीआरए परियोजनाओं के स्थलों पर भी धूल नियंत्रण के उपायों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों के अनुपालन में कमियां पाए जाने पर संबंधित परियोजना एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार के अनुसार, उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर निर्माण कार्य रोकने, बिजली आपूर्ति काटने और लागू

प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां नियमों का पालन किया जा रहा है, वहां निर्माण कार्यों में बाधा डालने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार शीतकालीन प्रदूषण कार्ययोजना के तहत प्रदूषण के स्रोतों पर समय रहते नियंत्रण स्थापित करने पर जोर दे रही है। एक अक्टूबर से वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ पहल भी मिशन मोड में लागू की गई है। इसके साथ ही वाहन उत्सर्जन, सड़क और निर्माण स्थलों की धूल,

औद्योगिक प्रदूषण, कचरा एवं जैविक अवशेष जलाने और प्रदूषण हॉटस्पॉट पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से तकनीक आधारित निगरानी मजबूत की गई है। वास्तविक समय में प्राप्त प्रदूषण संबंधी जानकारी के आधार पर जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया जा रहा है। निर्माण एजेंसियों को सामग्री और मलबे को ढककर रखने, नियमित पानी का छिड़काव करने, आवश्यकतानुसार एंटी-स्मॉग गन लगाने और उनका संचालन सुनिश्चित करने तथा धूल फैलाने से रोकने के लिए अवरोधक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही धूल निगरानी पोर्टल पर पंजीकरण और निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करना भी अनिवार्य है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल को नियंत्रित करना सरकार की प्रदूषण नियंत्रण रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डीपीसीसी लगातार निरीक्षण कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी परियोजनाओं में भी नियमों का उल्लंघन मिलने पर निजी परियोजनाओं की तरह कार्रवाई होगी। दिल्ली की हवा और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि है तथा नियमों के पालन में किसी को विशेष छूट नहीं दी जाएगी।

डीयू में तीसरा प्रोफेसर अशोक प्रसाद मेमोरियल लेक्चर, जल संरक्षण और सतत विकास पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के रसायन विज्ञान विभाग की ओर से प्रोफेसर अशोक प्रसाद मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट (पीएपीएमईटी) के सहयोग से शुक्रवार को सर शंकर लाल कॉन्सर्ट हॉल में तीसरा प्रोफेसर अशोक प्रसाद मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण, सतत विकास, वैज्ञानिक शोध, नवाचार और अपशिष्ट से उपयोगी संसाधन तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 400 से अधिक विद्यार्थी तथा 200 फैकल्टी सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रो. अशोक प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस अवसर पर ‘प्रोफेसर अशोक प्रसाद की यात्रा’ शीर्षक से एक लघु वृत्तचित्र प्रदर्शित किया गया, जिसमें उनके शैक्षणिक सफर, शोध में योगदान और छात्रों एवं शोधकर्ताओं की पीढ़ियों पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाया गया। कार्यक्रम में ‘वॉटरमैन ऑफ

इंडिया' के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और स्टैकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित डॉ. राजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई के पूर्व कुलपति पद्म प्रो. गणपति डी. यादव ने ‘वेस्ट टू वेल्थ’ विषय पर व्याख्यान दिया।

कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने प्रो. अशोक प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि एक शिक्षक की वास्तविक विरासत वे विद्यार्थी होते हैं, जिन्हें वह प्रेरित करता है, शिक्षा देता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है। उन्होंने अपने शिक्षक के सम्मान में ट्रस्ट की स्थापना करने के लिए प्रो. बी. के. सिंह की सराहना की। साथ ही, पीएपीएमईटी की ओर से छात्रवृत्तियों के माध्यम से वंचित पृष्ठभूमि के मेधावी विद्यार्थियों को सहायता करने की पहल का स्वागत किया। प्रो. सिंह ने विश्वविद्यालयों में शोध, शिक्षण और फैसल गतिविधियों के साथ स्थिरता को जोड़ने की

आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य एक स्वच्छ और टिकाऊ राष्ट्र के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार और उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर सोचने और समस्याओं को सार्थक कार्यों में बदलने की अपील की। पद्म प्रो. गणपति डी. यादव ने ‘वेस्ट टू वेल्थ’ विषय पर व्याख्यान देते हुए कृषि अवशेषों, नगरपालिका के ठोस कचरे, बेकार प्लास्टिक और औद्योगिक कार्बन को मूल्यवान कार्बन तथा उपयोगी आणविक निर्माण खंडों के स्रोत के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

उस्मानपुर में तीन महिलाओं की हत्याओं के आरोप से जावेद को बरी करने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी अदालत के एडिशनल सेशनस जज बलविंदर सिंह ने 2016 में उस्मानपुर में तीन हत्याओं के आरोपित जावेद को बरी करने का आदेश दिया। इस घटना में तीन महिलाओं मेहरुनिशा, उसकी मां सायरा और शबनम की गला काटकर हत्या की गई थी, जिसकी एफआईआर उस्मानपुर थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार हैदर नामक व्यक्ति का मेहरुनिशा से सम्बन्ध था। वह उसे आर्थिक मदद भी करता था। मेहरुनिशा ने उससे एक लाख रुपये की डिमांड यह कहकर की थी कि उसे किरायेदारों से ली गई पगड़ी की रकम लौटानी है। हैदर इन रुपयों का ईतजाम करने में विफल रहा, तो मेहरुनिशा ने उससे बातचीत बंद कर दी और अन्य लोगों के संपर्क में चली गई। इसके बाद हैदर और जावेद ने कथित तौर पर इन हत्याओं की साजिश रची। फैसले में वर्णित कथित योजना के अनुसार हैदर कथित तौर पर मेहरुनिशा की

गैरमौजूदगी में घर में घुस गया और सायरा तथा शबनम की मीट काटने वाले चाकू से हत्या कर दी। कथित तौर पर हैदर तब तक घर में टीवी देखता रहा। इसके बाद मेहरुनिशा के घर आते ही हैदर ने कथित तौर पर उसकी भी गला काटकर हत्या कर दी, लेकिन अदालत ने ठोस साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आरोपित जावेद को बरी कर दिया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह मौजूद हैं और वह आरोपितों के खिलाफ कथित आपराधों के कृत्यों को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है। जावेद द्वारा मोबाइल फोन को नष्ट करने के सिद्धांतों को पेश करने के अतिरिक्त इस दावे को साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया। इसके अलावा आरोपित को मोबाइल संपर्क नम्बर से जोड़ने के लिए कोई अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य अथवा वैज्ञानिक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं हैं।

डेंगू के बढ़ते मामलों पर एमसीडी अलर्ट, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने की समीक्षा बैठक

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को जन-स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डेंगू की रोकथाम, कीटनाशक दवाओं के भंडार, दवाओं की उपलब्धता तथा फॉगिंग व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम समयबद्ध तरीके से उठाए जाएं।

स्थायी समिति अध्यक्ष ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मंदिरों एवं रामलीला स्थलों के आसपास विशेष स्वच्छता और मच्छर नियंत्रण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर प्रदूषातुओं की बड़ी संख्या में आवाजही होती है, इसलिए आवश्यकतानुसार फॉगिंग कराई जाए और आसपास सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने नवरात्र के दौरान मंदिरों के आसपास मांस की दुकानों को बंद रखने के निर्देशों का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। सत्या शर्मा ने घर-घर निरीक्षण अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि एमटीएस एवं डीबीसी कर्मचारी नियमित रूप से घरों का निरीक्षण



करें और मच्छरों के प्रजनन की संभावित जगहों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि निरीक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो तथा लोगों को मच्छरों से बचाव के प्रति जागरूक भी किया जाए। उन्होंने जन-स्वास्थ्य विभाग को कीटनाशक दवाओं एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी कमी के कारण रोकथाम संबंधी कार्य प्रभावित न हों। साथ ही, प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार फॉगिंग और एंटी-लार्वा दवाओं का छिड़काव नियमित रूप से कराया जाए। बैठक में

एमटीएस कर्मचारियों के समान वेतन से संबंधित विषय की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सत्या शर्मा ने अधिकारियों से इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सत्या शर्मा ने कहा कि डेंगू एवं अन्य मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण, पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता, समय पर फॉगिंग और विभागीय समन्वय अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और जनस्वास्थ्य से जुड़े इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जेएनयू में शहरीकरण और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन पर जोर

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के आपदा प्रबंधन विभाग के सभागार में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ‘शहरीकरण, शासन और आपदा प्रबंधन: उभरती चुनौतियां और नीतिगत प्रतिक्रियाएं’ के समापन सत्र में शहरी आपदाओं, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। संगोष्ठी का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू कॉलेज (सांध्य), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के संयुक्त सहयोग से किया गया।

समापन सत्र की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कॉलेज (सांध्य) के प्राचार्य प्रो. संदीप गर्ग ने की। सत्र में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, वक्ता प्रो. राधे श्याम शर्मा तथा डॉ. दीप नारायण पांडेय उपस्थित रहे। डॉ. श्याम नारायण पांडेय ने स्वागत वक्तव्य में पूरे दिन सफलतापूर्वक आयोजित 17 से अधिक सत्रों, वक्ताओं, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने संगोष्ठी की सफलता का श्रेय मोतीलाल नेहरू कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों को दिया। वक्ता प्रो.



राधे श्याम शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के कारण आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ रही है। उन्होंने आपदा जोखिम कम करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, आर्कभूमियों और पर्यावरण के संरक्षण को आवश्यक बताया। उन्होंने चिकित्सा प्रगति के साथ जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सतत विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रेखांकित की। मुख्य अतिथि

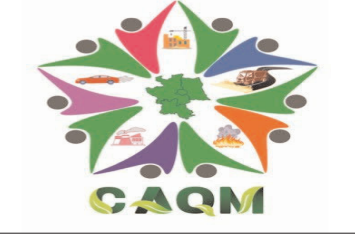
लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने आपदा प्रबंधन में भारतीय सेना की भूमिका, सामुदायिक सहभागिता और आपदा रोकथाम के महत्त्व पर बल दिया। उन्होंने दिल्ली में पिछले एक वर्ष के दौरान आग और भवन ढहने की 330 घटनाओं तथा अग्निकांडों में 65 प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख करते हुए सुरक्षा मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई। आगामी दशक में भारत की शहरी आबादी 55 करोड़ से अधिक होने की संभावना के संदर्भ में उन्होंने

पर्यावरण संरक्षण, भूकंपरोधी निर्माण और सुनियोजित शहरीकरण पर जोर दिया। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से आपदा प्रतिक्रिया तक सीमित रहने के बजाय रोकथाम और एकीकृत शासन व्यवस्था को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रो. संदीप गर्ग ने सुशासन, पर्यावरणीय स्थिरता और शोध निष्कर्षों को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने पर जोर दिया। उन्होंने भवन निर्माण, सीवेज, जल प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रभावी अनुपालन की आवश्यकता बताई। जापान के भूकंपरोधी निर्माण और नीदरलैंड के बाढ़ प्रबंधन से सीख लेते हुए उन्होंने आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने तथा संगोष्ठी के शोध निष्कर्षों को नीतिनिर्माताओं तक पहुंचाने पर बल दिया। अंत में डॉ. दीप नारायण पांडेय ने पर्यावरण संरक्षण को केवल वृक्षारोपण तक सीमित न रखकर प्रकृति के प्रति संवेदनशील व्यवहार और स्थानीय पर्यावरण के संरक्षण से जोड़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने विद्यार्थियों को सामूहिक प्रयास, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल विचारों और पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहार में लागू की जाने वाली जिम्मेदारी है।

एनसीआर की वायु गुणवत्ता प्रभावित करने वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए विशेषज्ञ उपसमिति गठित

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आसपास के क्षेत्रों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ उपसमिति का गठन किया है। यह समिति हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों की पहचान करेगी, जहां मौजूद प्रदूषण स्रोतों का असर एनसीआर और दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर पड़ रहा है। आयोग ने यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 11 की उपधारा (5) के तहत उठाया है। उपसमिति की अध्यक्षता सीएक्यूएम की तकनीकी सदस्य डॉ. एस.डी. अत्री करेंगी। समिति में आईआईटी (कानपुर) के प्रोफेसर-एमेरिटस मुकेश शर्मा, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर सागिनक डे, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के पूर्व कुलपति एस. के. सिंह, पीजीआईएमईआई को चंडीगढ़ के प्रोफेसर रविंद्र खैवाल और सीएसआईआर-नरी, दिल्ली के वैज्ञानिक ‘जी’ एवं प्रमुख एस. के. गोयल शामिल हैं। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ‘जी’ विजय सोनी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के



वैज्ञानिक ‘एफ’ सचिन घुड़े, टेरी की निदेशक (जलवायु परिवर्तन एवं वायु गुणवत्ता) सुरुचि भदवाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रसून गर्गावा तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य सचिवों को भी समिति में शामिल किया गया है। सीएक्यूएम के वैज्ञानिक ‘ई’ डॉ. विकास सिंह को उपसमिति का सदस्य-सचिव बनाया गया है। उपसमिति हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उन आसपास के क्षेत्रों की पहचान करेगी, जहां मौजूद प्रदूषण स्रोत एनसीआर की वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ इन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रमुख प्रदूषणकारी गतिविधियों का भी पता लगाया जाएगा। समिति के अध्यक्ष जरूरत के अनुसार अन्य विशेषज्ञों को भी उपसमिति में शामिल कर सकेंगे। आयोग ने उपसमिति को अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सौंपने का निर्देश दिया। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।

दिल्ली में प्रदर्शन से पहले करीब 75 ट्रेनें रद्द, इनमें 38 दिल्ली आने वाली

नई दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन और नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास यातायात बाधित होने की आशंका के मद्देनजर रेलवे ने करीब 75 ट्रेनों को रद्द किया है। इनमें 38 ट्रेनें ऐसी हैं, जिन्हें नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचना था। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उपाध्याय के अनुसार, इन दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 10 अक्टूबर की सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच पहुंचने वाली कुल 165 ट्रेनों में से 38 को रद्द किया गया है। शेष ट्रेनों के परिचालन पर इस निर्णय का असर नहीं पड़ेगा। आनंद विहार टर्मिनल, पुरानी दिल्ली, सराय रोहिल्ला और दिल्ली छावनी सहित दिल्ली के अन्य स्टेशनों पर ट्रेनों का परिचालन निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा। नौ अक्टूबर को दोपहर दो बजे के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली उन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द किया गया है, जिन्हें 10 अक्टूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचना था। रेलवे ने यह कदम दोनों स्टेशनों के आसपास भारी यातायात जाम की आशंका को देखते हुए उठाया है। रद्द की गई ट्रेनों में मगध एक्सप्रेस, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली आने वाली अन्य रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इस बीच, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस (12951) और मुंबई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन आने वाली अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस (12953) के प्रस्थान समय में पांच घंटे की देरी की गई है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी राष्ट्रीय ट्रेन पृष्ठताछ प्रणाली (एनटीईएस) से प्राप्त करने या हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने की अपील की है।

एमसीडी ने दिल्लीभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 28 स्थानों पर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई



सद्भावना टुडे, संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माणों तथा दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) और भवन उपनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध दिल्लीभर में व्यापक प्रवर्तन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। निगम के सभी 12 जोन में भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने और जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत एमसीडी ने 28 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तथा भवन निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर 6 संपत्तियों को सील किया। इससे पहले, कल भी निगम द्वारा 21 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और 4 संपत्तियों को सील किया गया था।

दिल्लीभर में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई
आज के प्रवर्तन अभियान के दौरान राजौरी गार्डन, विष्णु गार्डन, जनकपुरी, विकास नगर एक्सटेंशन, बाबा फरीद पुरी, करमपुरा, न्यू मोती नगर, मंडोली, हर्ष विहार, नेहरू विहार, राम नगर एक्सटेंशन, ज्योति कालोनी, पटपड़गंज गांव, मयूर विहार फेज-1 और गणेश नगर सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। एमसीडी ने स्पष्ट किया कि निगम के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को सतर्कता बनाए रखने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी), भवन उपनियमों और अन्य संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम का यह व्यापक प्रवर्तन अभियान अनाधिकृत निर्माणों, खतरनाक भवनों तथा जनसुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करने वाले अन्य उल्लंघनों के विरुद्ध लगातार जारी रहेगा। एमसीडी दिल्ली में भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षित शहरी वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक नजर

नूंह के गांव इंडरी की वर्षा पंवार बनीं सहायक प्रोफेसर, एमडीयू में हुआ चयन

नूंह,ए॰सेंसी। नूंह जिले के गांव इंडरी की बेटी वर्षा पंवार ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्षा पंवार का चयन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक में सोशियोलॉजी (समाजशास्त्र) विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी की लहर है, वहीं गांव में भी गर्व का माहौल बना हुआ है। वर्षा की सफलता को ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। वर्षा पंवार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के केएस पब्लिक हाई स्कूल से प्राप्त की और दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई द्रोणाचार्य कॉलेज, गुरुग्राम से पूरी की। शिक्षा के प्रति समर्पण, निरंतर मेहनत और अपने लक्ष्य को हासिल करने के दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। वर्षा के पिता रणधीर ने बेटी की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पूरे परिवार और गांव के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वर्षा ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया और दिन-रात मेहनत कर यह उपलब्धि हासिल की। उसकी सफलता से परिवार में उत्सव जैसा माहौल है और घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि गांव की बेटी का विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। वर्षा की उपलब्धि से अन्य बेटियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलेगी।

एटीडीसी व स्लेटेक मिलकर फैशन के विद्यार्थियों को देंगे एआई का प्रशिक्षण

गुरुग्राम। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए॰पी॰सी) द्वारा प्रवर्तित अपरेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी) ने फैशन एवं परिधान क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्लेटेक के साथ साझेदारी की है। जीमिमोड ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित स्लेटेक एआई आधारित फैशन कलेक्शन डिजाइन प्लेटफॉर्म है। एटीडीसी के राष्ट्रीय मुख्यालय अपरेल हाउस गुरुग्राम में आयोजित समारोह में शुक्रवार को संस्थान के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रो. (डॉ.) रूपक वशिष्ठ और स्लेटेक के निदेशक तनुज गंग्वानी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के तहत फैशन एवं परिधान क्षेत्र में स्लेटेक एआई फाउंडेशन माॅड्यूलस प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रशिक्षण में एटीडीसी के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सैद्धांतिक अध्ययन एवं मूल्यांकन के साथ स्लेटेक प्लेटफॉर्म पर व्यावहारिक अभ्यास भी शामिल होगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को एटीडीसी और स्लेटेक का संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यह कार्यक्रम शुरुआत में एटीडीसी के विद्यार्थियों के लिए पायलट आधार पर संचालित किया जाएगा। इसके बाद इसे संस्थान के प्रशिक्षण नेटवर्क में विस्तार देने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य फैशन की रचनात्मकता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और विद्यार्थियों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप डिजिटल कौशल प्रदान करना है।

पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या

फरीदाबाद। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेहतपुर इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच गुरुवार देर रात हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी हमले में वली मोहम्मद नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से लहलुहान अवस्था में वली मोहम्मद को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पल्ला थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

फरीदाबाद: ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत

फरीदाबाद। छांयसा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर खेत में पलट गये। हादसे में ट्रैक्टर चला रहा सतीश और उसके पालतू कुत्ते दोनों की मौत हो गई। सतीश ने करीब 12 साल पहले हरियाणा पुलिस की नौकरी छोड़ी थी। वह ट्रैक्टर-ट्राली में धान लेकर मोहना मंडी जा रहा था। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी था, जिसको सीट पर बैठाते समय ट्रैक्टर उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मोहना निवासी (45) सतीश धन से भरा ट्रैक्टर लेकर मोहना मंडी जा रहा था। उस के साथ ट्रैक्टर पर पालतू कुत्ता भी बैठा हुआ था। बताया गया है कि कुत्ते को सीट पर बैठाने के दौरान ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। ट्रैक्टर की रफ्तार तेज होने और उस पर धान का सामान ओवरलोड होने के कारण ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका।

गुरुग्राम नागरिक अस्पताल का ड्राइंग कार्य पूरा हुआ, जल्द निर्माण शुरु होगा: आरती सिंह राव

गुरुग्राम,ए॰सेंसी। हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि गुरुग्राम नागरिक अस्पताल का ड्राइंग कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के तहत धरातल पर कार्य का शुभारम्भ किया जाएगा। गुरुग्राम तेजी से विकसित हो रहा शहर है। भविष्य में इसकी आबादी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतें और बढ़ेंगी। ऐसे में हमारी प्राथमिकता है कि शहर के बढ़ते विस्तार और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को गुरुग्राम के वार्ड-15 में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास समारोह में बोल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हम राजनीति अपने लिए नहीं, बल्कि जनता



के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी जरूरतों को समझना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। आरती सिंह राव ने नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड 15 में 22 करोड़ की लागत के तीन महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इनमें सेक्टर-66 में

सड़कों के निर्माण, फुटपाथ एवं साइकिल ट्रैक विकसित करने तथा सीवरेज रहकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी जरूरतों को समझना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। आरती सिंह राव ने नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड 15 में 22 करोड़ की लागत के तीन महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इनमें सेक्टर-66 में

गाजियाबाद के लोनी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब, गोविंदपुरम में राहत की सांस



साहिबाबाद। जिले के लोनी क्षेत्र की हवा दूसरे दिन भी खराब श्रेणी में रही।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 256 दर्ज किया गया। वहीं, गोविंदपुरम के लोगों को सबसे अधिक राहत रही। यहां का एक्युआइ संतोषजनक श्रेणी में 59 दर्ज किया गया। संतोषजनक हवा में लोगों को सांस लेने में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। हालांकि गोविंदपुरम के लोगों को ज्यादातर दिन प्रदूषण से राहत रहती है। जिले की हवा तीन दिन से मध्यम श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन लोनी के लोगों को दो दिन से जहरीली हवा में रहना पड़ रहा है। यहां संचालित अवैध फैक्ट्रियां प्रदूषण को

सबसे अधिक बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा सड़कों पर उड़ती धूल, घरों में तार जलाकर निकाली जा रही धातु का कारोबार और निर्माण कार्य के कारण भी हवा जहरीली हो रही है।इससे यहां के लोगों में रोष है। लेकिन, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इन गतिविधियों को रोकने में फेल साबित हो रहे हैं। इसके अलावा इंदिरापुरम, संजय नगर, वसुंधरा, वेद विहार और वेव सिटी की हवा मध्यम श्रेणी से दर्ज की गई। यानी इन क्षेत्रों का एक्युआइ 200 से कम बना हुआ है। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि प्रदूषण रोकथाम के लिए निगरानी की जा रही है।

एमओटीपी नीति जल्द लागू करने की मांग, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन



नीति के लागू होने से अपने गृह जिलों में स्थानांतरण को अवसर मिलने की उम्मीद है। इससे उन्हें व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर भी राहत मिल सकती है। कमेटी ने कहा कि कर्मचारियों के हित में लिए गए सकारात्मक फैसलों से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली मजबूत होगी और जनसेवाओं को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। कर्मचारियों की जायज मांगों और समस्याओं

पर सरकार का सकारात्मक रुख सराहनीय है। कमेटी ने सरकार से आग्रह किया कि एमओटीपी नीति को बिना अनावश्यक देरी के लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि संबंधित कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। कमेटी ने सरकार के निर्णय का पुनः स्वागत करते हुए कर्मचारियों के हित में किए गए प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

गुरुग्राम: शिकायतों के समाधान में देरी पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही: उत्तम सिंह

गुरुग्राम। उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों की विभागवार निगरानी करते हुए उनका निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करें। जिन मामलों में अनावश्यक देरी हो रही है, उनमें संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने ये निर्देश शुक्रवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सीएम विडो, सीएम जन संवाद, सीपीग्राम्स और समाधान शिविरों सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान दिए।

उन्होंने कहा कि शिकायतों पर कार्रवाई का उद्देश्य केवल पोर्टल पर स्थिति अपडेट करना नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान करना होना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में शिकायतों के प्रभावी समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनने तथा शिकायतकर्ताओं को

बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में शिकायतों की सुनवाई निर्बाध रूप से जारी रहनी चाहिए। यदि एसडीएम अवकाश पर हों या किसी बैठक के लिए बाहर जा रहे हों, तो वे पहले से ही किसी अन्य सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सीएम विडो, निर्धारित करें, ताकि शिविर में आने वाले लोगों की शिकायतों की सुनवाई प्रभावित न हो और उन्हें समय पर उचित समाधान मिल सके। डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि दोबारा खोली गई शिकायतें को समीक्षा करते समय पहले की गई कार्रवाई और शिकायत दोबारा खुलने के कारणों की जांच की जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पहले की कार्रवाई में रह गई कमियों को दूर करते हुए शिकायत का उचित समाधान किया जाए। एक से अधिक विभागों से जुड़ी शिकायतों में संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें। साथ ही, शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जाए।

सड़कों का बीएम एवं बीसी तकनीक से पुनर्वास कार्य शामिल है। इन विकास परियोजनाओं से क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ-साथ नागरिकों को सुगम आवागमन, बेहतर जल निकासी और आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आरती सिंह राव ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु बनें, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और लोगों को अपने छोटे-बड़े कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों की मांग के अनुरूप स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार, चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

विभिन्न सड़क हादसों मे चार लोगों की मौत

अशोक कुमार, सदभावना टुडे नोएडा। नोएडा में अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों मे चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना इकोटेक प्रथम के प्रभारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मूलरूप से बुलंदशहर निवासी धर्मेन्द्र (30) गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन थे। गुरुवार की देर रात को वह बाइक से घर जा रहे थे। उनकी बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें उनकी मौत हो गई।पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सेक्टर 58 के प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि गुरुवार की देर रात को बसती देवी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति धर्मराज भारद्वाज ड्यूटी करने के लिए आठ अक्टूबर को सेक्टर 62 जा रहे थे। इसी दौरान इंडस वैली लाल बत्ती के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दिया। महिला के अनुसार, उन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर गुरुवार की रात को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सेक्टर- 24 के प्रभारी उमेश तैथानी ने बताया कि राजेंद्र सिंह ने शुक्रवार सुबह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह झुंडपुरा गांव सेक्टर 11 में रहते हैं। उनका भाई



सोमपाल सिंह भी उनके साथ रहता है। 7 अक्टूबर की देर रात को सेक्टर 11 स्थित कंपनी से काम करके अपने घर लौट रहे थे।तभी एक अज्ञात बोलेरो पिकअप के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सेक्टर 11 के पास उन्हें टक्कर मार दिया। पीड़ित के अनुसार इस घटना में उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको उपचार के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बीती रात को उनकी मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मूलरूप से हापुड़ के रज्जाकपुर गांव निवासी जयपाल सिंह का बेटा विवेक नोएडा में बाउंसर के रूप में काम करता था। वह दादरी क्षेत्र के घोड़ी

बछेड़ा गांव में किराए के मकान में रहता था। उन्होंने बताया कि बीती रात को दोवतों के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। देर रात को सेक्टर ओमिक्रॉन के पास विवेक सड़क पर लहलुहान हालत में पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि सड़क किनारे लड़े सबमर्सिबल पंप के टैंक से टकराने पर युवक की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

फरीदाबाद में बाउंसर की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या

फरीदाबाद। तिलपत गांव में 25 वर्षीय बाउंसर की लोहे ही रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। जिसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मृतक की पहचान नूंह जिले के गांव बीसरू के रहने वाले वली मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव तिलपत के रहने वाले ताहिर ने शुक्रवार को बताया कि गांव में उनके नए घर का प्रोग्राम था। गुरुवार रात्रि उनके घर पर प्रोग्राम चल रहा था। पड़ोसी युवक ने ताहिर के भतीजे में बाइक से टक्कर मार दी। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। परिवार के लोगों में झगड़ा बढ़ते देख उनका भांजा वली मोहम्मद (25) बीच बचाव के लिए चला गया। लेकिन आरोपियों ने उस पर लोहे की रॉड से वार करना शुरू कर दिया। मृतक के मामा ताहिर ने बताया कि उसका भांजा 4 साल बाद उनके घर पर आया था। आरोप है साहिल ने उसके ऊपर लगातार लोहे की रॉड से वार किए। उसके सर पर कई वार किए गए।

नूंह के रोजगार मेले में सात सौ युवाओं को मिला रोजगार

नूंह। नूंह जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), नूंह के तत्वावधान में शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नल्हड़ में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 52 कंपनियों ने भाग लिया और कुल 707 युवाओं को जॉइनिंग लेटर विहारित किए गए। इनमें 145 युवाओं को अप्रेंटिसशिप तथा 564 युवाओं को नियमित वेतन वाली नौकरियों के लिए जॉइनिंग लेटर मिले। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नूंह जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं, एसडीएम कुंवर आदित्य कुमार सिंह और मंडलीय रोजगार अधिकारी योगेश कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहे। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों ने युवाओं की योग्यता और तकनीकी दक्षता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके कौशल का उपयोग सुनिश्चित करना रहा। विभिन्न कंपनियों की भागीदारी से युवाओं को



अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार चुनने का अवसर मिला। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को कार्यक्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, वहीं नियमित वेतन वाली नौकरियों से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के बीच की दूरी कम करने का

अवसर मिला। रोजगार प्राप्त करने वाले युवा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकेंगे। ऐसे रोजगार मेले तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को कंपनियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को उचित अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ढाई दशक के सख्त फैसलों ने मोदी को बनाया मजबूत नेतृत्वकर्ता

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ढाई दशक की अनवरत राजनीतिक नेतृत्व यात्रा के दौरान लिए गए एक से एक चौंकाने वाले फैसलों ने मोदी को मोदी बनाया है। आज मोदी विश्व के सर्वाधिक भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। सामने वाले को भी यह भय सताये रहता है कि पता नहीं मोदी क्या स्टैंड लेकर क्या का क्या कर डालेंगे। यही कारण है कि चाहे डोनाल्ड ट्रम्प हो, पुतिन हो या फिर शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री को हल्के में नहीं ले पाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के आगे भारत नहीं झुका है तो रूस से कच्चे तेल का आयात जारी है। मालदीव का उदाहरण सामने है जब नरेन्द्र मोदी ने भारत के द्वीप पर केवल कुर्सी लगाकर बैठकर ही मालदीव को हिला कर रख दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में करीब 13 साल और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल से कुछ अधिक के समय में लिए गए निर्णयों से समूचे विपक्ष को धीरे से लेकिन जोर का झटका देते रहे हैं। हो यह रहा है कि नरेन्द्र मोदी पर जो भी वार किया जाता है वही वार नरेन्द्र मोदी की ताकत बन जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते गोदारा कांड की बात हो या फिर चौकीदार चोर से लेकर वोट चोरी तक की हो, प्रतिपक्ष का हर वार ना केवल खाली गया है अपितु प्रतिपक्ष के लिए सेल्फ गोल बनकर रह गया। देश आज आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोपरि होकर उभरा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल में ही अपने दूरगामी निर्णयों से विशिष्ट पहचान बना ली थी। चाहे वह गोदारा कांड हो या फिर गुजरात भूकंप और उसके बाद विनाशकारी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण के कार्य, नर्मदा के अतिरिक्त पानी को पाइपलाइन के माध्यम से उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के सुखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ भारत का सपना भी गुजरात के रास्ते ही आया है तो कृषि और घरेलू जरूरत की बिजली की व्यवस्था को अलग अलग कर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना अपने आप में बड़ी बात है। वाईब्रेंट गुजरात समिट को देशी-विदेशी निवेश को सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से साकार करना किसी दूरगामी सोच का ही परिणाम है। आज देश के अनेक राज्यों में निवेश सम्मेलन होने लगे हैं और ईज ऑफ डूइंग के बावजूद गुजरात समिट को मॉडल समिट माना जाता है। आज का मेक इन इंडिया इसी का



विस्तार है। जहां तक प्रधानमंत्री बनने के बाद के निर्णयों का सवाल है तो कूटनीति और विदेश नीति के मोर्चे पर आज भारत की तूती बोलती है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिन्दूर ने समूची दुनिया के सामने भारत के रण कौशल की धाक जमा दी और इसका परिणाम यह रहा कि पाकिस्तान के पक्ष

में आवाज उठाने की हिम्मत अन्य देशों में नहीं रही। कहने को तुर्किए पाकिस्तान के पक्ष में गाहे-बेगाहे बोलता है पर उसका असर नागण्य है। ब्रिक्स के माध्यम से आज भारत दुनिया के देशों का नेतृत्व कर रहा है तो अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की शुरुआत भारत के नेतृत्व में दुनिया के देश करने लगे हैं। देर-सबेर यह

हालात होंगे ही। समान नागरिकता कानून और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ना लगभग असंभव काम हो सका है।

आर्थिक क्षेत्र में आज भारत दुनिया की प्रमुख ताकत बनकर उभरा है। एक राष्ट्र एक कर जीएसटी विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद आज इकोनोमी का

प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। नोटबंदी का लाख विरोध हुआ और जनधन, आधार और मोबाइल यानी की जाम का असर साफ दिखाई दे रहा है। आज मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में भारत अग्रणी देश हो गया है। मेक इन इंडिया और वोकरा फॉर लोकल ने असर दिखाया है तो सुधार प्रयासों का ही परिणाम है हमारे देश से आज सामरिक महत्व के उत्पादों का निर्यात होने लगा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना ने एमएसएमई को नई ताकत दी है। न्यायिक क्षेत्र के सुधार सामने हैं। पुराने अनावश्यक कानूनों को हटाया गया है तो आज के संदर्भ में नई भारतीय न्याय संहिता लागू की है। चार श्रम कानूनों के माध्यम से श्रमिकों के भविष्य को संवारने का काम किया गया है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने राममंदिर का निर्माण कराकर स्पष्ट संदेश दे दिया कि भाजपा के नारे या वादे ख्याली पुलाव नहीं होते। बिना किसी विवाद के राममंदिर विवाद का निपटारा बहुत बड़ी उपलब्धी मानी जानी चाहिए। तीन तलाक का बिल पारित कराना अपने आप में मुश्किल भरा काम था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में 33 प्रतिशत आरक्षण महिला सशक्तिकरण का बड़ा निर्णय माना जाना चाहिए। कोविड 2019 के दौरान भारत द्वारा किये गये प्रबंधन को वैश्विक सहयोग को दुनिया के कई देशों द्वारा सराहा गया। आयुष्मान भारत, कृषि और कृषक सम्मान के निर्णय, पीएम गरीब कल्याण योजना या इसी तरह के कार्यक्रमों और निर्णयों की लंबी फेहरिस्त हो जाती है। सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 साल के अपने राजनीतिक नेतृत्व के दौरान क्या किया। सवाल यह है कि आज भारत दुनिया के देशों का पिछलगू ना होकर दुनिया भारत की ओर देखने लगी है। भारत अपने स्तर पर अपनी आवश्यकताओं और संप्रभुता बनाये रखते हुए निर्णय लेता है। नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रहते जो कठोर निर्णय लिए गए हैं उनमें से अधिकांश दुधारी निर्णय रहे हैं और खास बात यह है कि चुनावों में जनता द्वारा उन पर मुहर लगाई जा रही है। इसलिए विपक्ष लाख आलोचना करे पर इसमें दो राय नहीं कि 25 साल की यात्रा और विपक्ष के तीखे हमलों के बावजूद नरेन्द्र मोदी जनता के भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि निर्णय करना और खासतौर से कठोर निर्णय जोखिम भरा होता है पर प्रत्येक कठोर निर्णय के बाद नरेन्द्र मोदी और अधिक निखर के आये हैं।

निजी कंपनियां पूंजी, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीकी सोच लेकर आती हैं। इससे लॉन्च, उपग्रह निर्माण और डेटा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए उद्यम उमरते हैं, रोजगार बढ़ता है और भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में बड़ा खिलाड़ी बनने की स्थिति में आता है। दूसरी ओर इस निर्णय का विरोध करने वालों की आशंकाएं स्वाभाविक हैं पर उनका उत्तर तथ्यों और व्यवस्था के स्वरूप में मौजूद है। पहली आशंका जो दिखती है, वह है कि क्या इसरो की भूमिका कमजोर होगी? जबकि ऐसा नहीं है। निजी भागीदारी सरकारी संस्थान का विकल्प कैसे हो सकती है, हां, उसका पूरक अवयव बन सकती है। इसरो एगनीतिक और अनुसंधान मिशनो का नेतृत्व जारी रखेगा ही, जबकि वाणिज्यिक और सेवा आधारित कामों का बोझ निजी क्षेत्र उठा सकता है। इससे इसरो के संसाधन और वैज्ञानिक प्रतिभा गहरे अनुसंधान और बड़े मिशनो पर केंद्रित हो पाएंगे। एक आशंका, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी नियंत्रण पर पड़ने वाले असर से जुड़ी है, जिसमें कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र का मतलब नीतिगत नियंत्रण का अभाव है, जबकि सरकार नीति, नियमन और बुनियादी ढांचे की भूमिका में बनी रहती है। वास्तव में यह सोच सही इसलिए नहीं है क्योंकि सबकुछ अंततः सरकार के नियंत्रण में ही रहता है। इसी प्रकार यह कहना कि निजी कंपनियां केवल मुनाफे पर ध्यान देंगी, राष्ट्रीय हित पर नहीं- इसका उत्तर नहीं- इसका उत्तर भारत का अपना अनुभव है। चंद्रयान-3 ने दिखाया कि देश उल्लेखनीय लागत दक्षता के साथ परिष्कृत मिशन चला सकता है।

भारत ने अंतरिक्ष के द्वार निजी क्षेत्र के लिए क्यों खोले?

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

दशकों तक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सरकारी संस्थाओं की सीमाओं में चलता रहा। इसरो ने सीमित संसाधनों में चंद्रयान और मंगलयान जैसी उपलब्धियां हासिल कीं पर देश की युवा प्रतिभाओं के लिए अवसर गिने-चुने थे। मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलकर इसी उद्देश्य को तोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। वाराणसी में नमो बुक फेस्ट के दौरान छात्रों से संवाद में रखे गए तथ्य और तर्क बताते हैं कि यह निर्णय कितना दूरदर्शी सिद्ध हुआ है। वस्तुतः इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ मानव संसाधन के मोर्चे पर दिखता है। पहले घरेलू अंतरिक्ष इकोसिस्टम में अवसर सीमित थे इसलिए अनेक युवा पेशेवर विदेश की ओर देखते थे। क्षेत्र खुलने के बाद अधिक प्रतिभाएं देश में रहकर भारत के बढ़ते अंतरिक्ष तंत्र में योगदान दे पा रही हैं। यह तो हमें ही समझना होगा कि एक इंजीनियर को प्रशिक्षित करने में देश का सार्वजनिक धन और संस्थागत श्रम लागता है। वही इंजीनियर जब विदेशी कंपनियों के लिए काम करता है तो उसका लाभ दूसरे देश को मिलता है। निजी क्षेत्र के खुलने से यह प्रवाह थमा और स्कार्ईरूट जैसे अंतरिक्ष स्टार्टअप युवा इंजीनियरों को अपने ही देश में चुनौतीपूर्ण काम और नवाचार का मंच दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमें समझना यह भी है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब लगभग नौ बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। यदि मौजूदा गति बनी रही, तो अगले 8-10 वर्षों में यह 45-46 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है यानी लगभग पांच गुना विस्तार। इस वृद्धि का श्रेय क्षेत्र को खोलने और हितधारकों की व्यापक श्रृंखला को जोड़ने को दिया जा रहा है। यह तर्कसंगत भी है क्योंकि एक संस्था पर सारा भार होने की स्थिति में विकास की गति उसकी क्षमता से बंध जाती है।

निजी कंपनियां पूंजी, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीकी सोच लेकर आती हैं। इससे लॉन्च, उपग्रह निर्माण और डेटा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए उद्यम उभरते हैं, रोजगार बढ़ता है और भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में बड़ा खिलाड़ी बनने की स्थिति में आता है। दूसरी ओर इस निर्णय का विरोध करने वालों की आशंकाएं स्वाभाविक हैं पर उनका उत्तर तथ्यों और व्यवस्था के स्वरूप में मौजूद है। पहली आशंका जो दिखती है, वह है कि क्या इसरो की भूमिका कमजोर होगी? जबकि ऐसा नहीं है। निजी भागीदारी सरकारी संस्थान का विकल्प कैसे हो सकती है, हां, उसका पूरक अवयव बन सकती है। इसरो एगनीतिक और अनुसंधान मिशनो का नेतृत्व जारी रखेगा ही, जबकि वाणिज्यिक और सेवा आधारित कामों का बोझ निजी क्षेत्र उठा सकता है। इससे इसरो के संसाधन और वैज्ञानिक प्रतिभा गहरे अनुसंधान और बड़े मिशनो पर केंद्रित हो पाएंगे। एक आशंका, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी नियंत्रण पर पड़ने वाले असर से जुड़ी है, जिसमें कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र का मतलब नीतिगत नियंत्रण का अभाव है, जबकि सरकार नीति, नियमन और बुनियादी ढांचे की भूमिका में बनी रहती है। वास्तव में यह सोच सही इसलिए नहीं है क्योंकि सबकुछ अंततः सरकार के नियंत्रण में ही रहता है। इसी प्रकार यह कहना कि निजी कंपनियां केवल मुनाफे पर ध्यान देंगी, राष्ट्रीय हित पर नहीं- इसका उत्तर भारत का अपना अनुभव है। चंद्रयान-3 ने दिखाया कि देश उल्लेखनीय लागत दक्षता के साथ परिष्कृत मिशन चला सकता है। यही दक्षता निजी उद्यमों के साथ जुड़कर भारत को किफायती और विश्वसनीय वैश्विक साझेदार बनाती है। जैव प्रौद्योगिकी में कोविड-



19 के विरुद्ध दुनिया के पहले डीएनए टीके का विकास यह भी दिखाता है कि नीतिगत समर्थन मिलने पर भारतीय संस्थान और उद्योग राष्ट्रीय उपलब्धि में बदल सकते हैं। इसी तरह से बात जब लाभ की होती है और कहा जाता है कि कुछ बड़े समूहों तक ही यह सीमित रहेगा? यहां स्टार्टअप की भूमिका निर्णायक है। स्कार्ईरूट जैसे नवोदित उद्यमों का उदय बताता है कि अवसर बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित नहीं हैं। छोटे शहरों और संस्थानों से निकले युवा इंजीनियरों के लिए भी अब अपना उद्यम खड़ा करने का मार्ग खुला है। अंततः फिर भी जो सवाल उठते हैं, उनसे पूछा जाए कि फिर आपके पास विकल्प क्या है, समाधान बताएं, प्रश्न ही न करें।

वस्तुतः यही वास्तविकता है कि यदि क्षेत्र बंद रहता तो प्रतिभा विदेश जाती रहती, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संभावनाएं एक संस्था की क्षमता में सिमटी रहतीं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत पिछड़ने का जोखिम उठता रहता। ऐसे में कहना यही है कि सरकार की दृष्टि स्पष्ट है, सरकारी संस्थानों, निजी उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और शोध संस्थानों को साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। अक्सर अलग-अलग दीवारों में बंद रहकर काम करने से संसाधनों का दोहराव होता है और ज्ञान का प्रवाह रुकता है। जब सरकार नीति और बुनियादी ढांचा देती है, उद्योग गति और नवाचार लाता है और शिक्षा जगत अनुसंधान तथा कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराता है तब ऐसी क्षमताएं बनती हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। पिछले 12-13 वर्षों को भारत में 'विज्ञान का युग' कहा जा रहा है। देश के पास दशकों से वैज्ञानिक प्रतिभा थी, पर उसे राष्ट्रीय क्षमता में बदलने वाला सक्षम नीतिगत वातावरण हाल के वर्षों में मजबूत हुआ है। अंतरिक्ष क्षेत्र का उद्घाटन इसी व्यापक सोच का

हिस्सा है, जिसमें डीप ओशन मिशन, क्वांटम मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी पहलें भी शामिल हैं। इसका प्रमाण अनुसंधान पर बढ़ते निवेश में भी दिखता है। देश का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (जीईआरडी) 2013-14 के लगभग 46,000-47,000 करोड़ रुपये से बढ़कर अब लगभग 2-2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी क्रम में परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला गया है और 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जो एआई और डेटा केंद्रों जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बनेगा। भारत की वैज्ञानिक प्रगति ने देश में नया आत्मविश्वास पैदा किया है, जो उसकी बढ़ती वैश्विक स्थिति और युवाओं को उपलब्ध अवसरों में दिखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश 'हम यह कर सकते हैं' आज इसी भाव का प्रतीक है। भारत अब दुनिया का अनुसरण करने वाले चरण से आगे बढ़कर दुनिया के साथ कदम मिला रहा है और कई क्षेत्रों में आगे भी है। यह सफर तकनीक के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ ही सार्थक है। प्रौद्योगिकी को मानव क्षमता का स्थान नहीं लेना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए। यही दृष्टि अंतरिक्ष क्षेत्र पर भी लागू होती है, जहां निजी भागीदारी का उद्देश्य जिज्ञासा और वैज्ञानिक खोज की भावना को और बल देना है। हम उम्मीद करें कि आगे की सफलता निरंतर सहयोग, युवाओं के लिए अधिक अवसरों और वैज्ञानिक क्षमता को नवाचार तथा आर्थिक अवसर में बदलने पर निर्भर करेगी। विकसित भारत का लक्ष्य सामूहिक भागीदारी से ही प्राप्त होगा यह सुनिश्चित है इसलिए अंतरिक्ष के द्वार खोलना इसी दिशा में उठाया गया मोदी सरकार का ठोस कदम है।

विचार

कांग्रेस और सीजेपी के प्रदर्शनों के चलते दिल्ली में व्यापार ठप

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली में राजनीतिक प्रदर्शनों और सुरक्षा व्यवस्था के चलते यातायात पर लग रही पाबंदियों का असर अब केवल आम यात्रियों तक सीमित नहीं रह गया है। राजधानी के बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही घटने, कारोबार प्रभावित होने और दूसरे शहरों से खरीदारी के लिए आने वाले व्यापारियों की संख्या कम होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। चिंता इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नवरात्रि से दिवाली तक का समय खुदरा कारोबार, थोक खरीदारी, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषणों, सजावटी सामान और शादी-ब्याह की खरीदारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली के व्यापारिक संगठनों के ताजा दावों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में बाजारों की कारोबारी गतिविधियां लगभग 70 प्रतिशत तक गिर गई हैं। यह स्थिति बताती है कि सड़कों पर लगने वाली पाबंदियों और मेट्रो सेवाओं में व्यवधान का आर्थिक असर कितना व्यापक हो सकता है। हम आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के दौरान राजघाट और कर्नाट प्लेस के आसपास यातायात बाधित हुआ। इसके चलते, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के रास्ते बंद होने और ट्रेफिक प्रतिबंधों के कारण 5,000 से अधिक यात्री अपनी ट्रेनें नहीं पकड़ सके। साथ ही इस घटना का सीधा संबंध व्यापारिक नुकसान से भी है। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले कारोबारी अवसर ट्रेन से पहुंचते हैं। उन्हें स्टेशन से थोक बाजारों तक जाना होता है, माल खरीदना होता है और फिर निर्धारित समय में वापसी करनी होती है। जब स्टेशन तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाए, तो उनकी यात्रा, खरीदारी और माल की ढुलाई तीनों प्रभावित होती हैं। कांग्रेस के प्रदर्शनों के ठीक बाद अब 10 अक्टूबर को सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। देखा जाये तो सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन जब बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन, मेट्रो स्टेशन के प्रवेश-द्वारों पर प्रतिबंध और बाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण जैसे कदम व्यावसायिक इलाकों को प्रभावित करते हैं, तो उनका आर्थिक असर भी होता है।

विशेष चिंता यह है कि नई दिल्ली, कर्नाट प्लेस, जनपथ और आसपास के बाजारों में ग्राहक पहुंचने से कतराने लगते हैं। ग्राहक यह सोचकर खरीदारी टाल देते हैं कि बाजार पहुंचना और वहां से लौटना मुश्किल होगा। यहां नुकसान केवल उस दिन की बिक्री का नहीं है। दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति, माल की डिलीवरी, थोक खरीदारों की यात्राएं, रेस्तरां की बिक्री और पार्किंग पर निर्भर कारोबारी गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। देखा जाये तो दिल्ली के व्यापारियों की चिंता का सबसे बड़ा कारण समय है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं। इसके बाद रामलीला, दशहरा, दिवाली और शादी-ब्याह का सीजन कारोबार को गति देते हैं। इस दौरान कपड़े, साड़ियां, रेडीमेड गारमेंट, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, सजावट के सामान, पूजा सामग्री, आभूषण और उपहारों की मांग बढ़ती है। दिल्ली के बाजार केवल राजधानी के स्थानीय ग्राहकों पर निर्भर नहीं हैं। देश के अनेक शहरों और कितना हो सकता है? इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण करने के लिए छूट तथा विशेष सेल चलाते हैं। ऐसे में यदि बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बाधित होती है, तो माल दुकान में पड़ा रह सकता है। व्यापारी को किराया, कर्मचारियों का वेतन, बिजली, परिवहन और स्टॉक पर लगी पूंजी की लागत फिर भी चुकानी पड़ती है। यहां सवाल उठता है कि प्रदर्शनों के चलते आखिर व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ और कितना हो सकता है? इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण आधार चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (एडइडू) का 9 अक्टूबर को सामने आया आकलन है। संगठन ने अपने सर्वे के हवाले से कहा है कि पिछले तीन दिनों में दिल्ली के बाजारों की कारोबारी गतिविधियों में करीब 70 प्रतिशत गिरावट आई है। एडइडू के अनुसार, दिल्ली से बाहर से खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों की संख्या सामान्य अनुमानित 2 से 3 लाख प्रतिदिन से घटकर करीब 40,000 से 50,000 रह गई। स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही भी 50 प्रतिशत से अधिक कम होने का दावा किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि एडइडू ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में नवरात्रि से दिवाली तक प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में बड़े प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें नियंत्रित करने की मांग की है।

एक नजर

हथियार के बल पर स्वर्ण त्यवसायी से लाखों के जेवरात व नकदी लूटे, विरोध करने पर पिस्टल के बट से किया घायल



सीवान,एजेंसी। दरौंदा थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शुक्रवार की शाम जलालपुर और कमला चौक के बीच बाइक सवार दो अपराधियों ने हथियार के बल पर एक स्वर्ण व्यवसायी को घेरकर लाखों रुपये मूल्य के जेवरात और नकदी लूट लिये। विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल के बट से हमला कर व्यवसायी को घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी महाराजगंज की ओर फरार हो गये। सरेशाम हुई इस लूट की घटना से इलाके में दहशत फैल गयी है, वहीं स्वर्ण व्यवसायियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गयी है। मिली जानकारी के अनुसार, जलालपुर निवासी शिवजी प्रसाद के पुत्र रत्नेश कुमार चन्चौरा बाजार में शिव ज्वैलर्स नाम से आभूषण की दुकान चलाते हैं।

शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे दुकान बंद करने के बाद वह बाइक से अपने घर जलालपुर लौट रहे थे। इसी दौरान जलालपुर और कमला चौक के बीच बाइक सवार दो अपराधियों ने ओवरटेक कर उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर उनके पास मौजूद जेवरात और नकदी लूटने का प्रयास किया। रत्नेश कुमार ने जब लूटपाट का विरोध किया, तो बदमाशों ने पिस्टल के बट से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद अपराधी लाखों रुपये मूल्य के जेवरात और नकदी लेकर बाइक से महाराजगंज की ओर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही दरौंदा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आपसपास के क्षेत्रों में छानबीन कर रही है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली थी। सरेशाम स्वर्ण व्यवसायी से हुई इस लूट ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और व्यवसायियों की सुरक्षा पर ख़ास खड़े कर दिये हैं। स्थानीय लोगों के बीच भी घटना को लेकर भय का माहौल है।

छपरा विधायक ने ब्रह्मपुर–बिशुनपुरा पथ की बदहाली पर पथ निर्माण मंत्री को सौपा पत्र



सारण,एजेंसी। शहर के व्यस्त ब्रह्मपुर-बिशुनपुरा पथ पर बने गड्ढों को लेकर विधायक छोटी कुमारी ने दुर्गापूजा से पहले तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने और गुणवत्तापूर्ण मरम्मत सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। विधायक ने चिंता जताते हुए कहा कि इस सड़क से दुर्गापूजा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। वर्तमान में सड़क की बदहाल स्थिति किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राथमिकता देने के बजाय केवल उन हिस्सों में हल्की मरम्मत की जा रही है, जहां इसकी खास जरूरत नहीं है, जबकि मुख्य गड्ढे जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से लगातार अधिकारियों से अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने खुद जिला अभियंता से स्थलीय निरीक्षण कराकर खतरनाक गड्ढों की स्थिति दिखाई थी, इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से दोपहिया चालकों, टोटो, छोटी गाड़ियों और पैदल यात्रियों के लिए खतरा और बढ़ गया है। विधायक छोटी कुमारी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। अनियमितता पाए जाने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

रत्नातक से 40 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 13 अभ्यर्थी मैदान में



दरभंगा। बिहार विधान परिषद के 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 40 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 13 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। शुक्रवार को प्रमंडलीय सभागार में निर्वाची पदाधिकारी-सह-आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1,26,951 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 9,026 मतदाता पंजीकृत हैं। स्नातक निर्वाचन के लिए 138 और शिक्षक निर्वाचन के लिए 99 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्नातक निर्वाचन में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय में क्रमशः 43, 32, 34 और 29 मतदान केंद्र हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन के लिए इन जिलों में क्रमशः 32, 23, 24 और 20 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन कर्मियों के तीन चरणों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया।

‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ को तेजी से पूरा करें विभाग : सम्राट चौधरी



पटना,एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ तेजी से और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता तथा समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास पर

अभियान की प्रगति और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, बस अड्डों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार के लिए रंग-रोगन, चहारदीवारी निर्माण और मरम्मती कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बेहतर शौचालय, शुद्ध पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित

स्मैक तस्करी के तीन अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य गिरफ्तार

अररिया,एजेंसी।

एसपी जितेंद्र कुमार के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों के कारोबार और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने 300 ग्राम स्मैक के साथ मादक पदार्थों के तस्करी के अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया।अररिया आरएस थाना पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर अररिया गलगलिया रेल लाइन के पास स्मैक आदान प्रदान करने के समय कार्रवाई करते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल संख्या

बीआर 38 एआर 8982 और चार स्मार्ट फोन के साथ पांच सौ रुपये नगद भी बरामद किया।जानकारी के अनुसार एसडीपीओ ने शुक्रवार के शाम को अपने कार्यालय कक्ष में अररिया के पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि फारबिसगंज के छुवापट्टी चौक स्थित मेसर्स गणेश भंडार उनकी कंपनी के रजिस्टर्ड ब्रांड और नाम का रोलत इस्तेमाल कर चावल बेच रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी फर्म कई सालों से चावल बना रही है। गणेश भंडार द्वारा उनके ब्रांड की नकल करने से उनके ब्रांडिंग और व्यापार पर असर पड़ रहा था।श्री



घेराबंदी कर दीपू मल्लिक,पवन कुमार यादव और वसीम शेख को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से तीन जिपर में तीन सौ ग्राम स्मैक बरामद किया गया।मामले में अररिया के पुलिस अधीक्षक और 111 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है। सदर एसडीपीओ ने बताया कि दीपू मल्लिक का पुराना आपराधिक इतिहास है। जोगबनी,डगरूआ और अररिया थाना में कुल सात मादक पदार्थों की तस्करी और कारोबार और अन्य संगीन मामलों में केस दर्ज है।

मुजफ्फरपुर रेल पुलिस का विशेष अभियान, 31 ट्रेनों में सघन जांच, 312 बेटिकट यात्रियों से वसूले गए 1.93 लाख रुपये



मुजफ्फरपुर। जिले में आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए रेल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और रेल परिसर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान डींग स्क्वाड, आरपीएफ और टिकट जांच कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित कर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सघन जांच की जा रही है। दरअसल, 8 अक्टूबर को चलाए गए विशेष अभियान के तहत रेल जिला मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली कुल 31 ट्रेनों में जांच की गई। इस दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे 312 यात्रियों को पकड़ा गया। टिकट जांच के क्रम में इन यात्रियों से कुल 1 लाख 93 हजार 800

रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, ट्रेनों में अवैध रूप से सामान बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। रेल पुलिस के अनुसार, बिहार पुलिस अभियान 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और रेल परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। वहीं, पूरे मामले पर रेल एसपी वीणा कुमारी ने बताया कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा जैसे पर्व-त्योहारों के मद्देनजर रेल पुलिस पूरी तरह सतर्क है।

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। रेल पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें और रेलवे के नियमों का पालन करें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल रेल पुलिस को सूचित करें। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने कहा है कि पर्व-त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ विशेष जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण और राहत कार्यों का सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की समीक्षा,अधिकारियों को दिए कई निर्देश

सारण। अमनौर स्थित अपने आवास पर सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ के बाद उत्पन्न परिस्थितियों और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना, क्षति का सटीक आकलन करना और जिले के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना था। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी नीतेश कुमार, मझौरा के सैयद अदील मोहसिन और सोनपुर की सिन्धा नेहा के साथ-साथ सिविल सर्जन डॉ के चौधरी और विभिन्न विभागों के अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में सांसद रूडी ने बताया कि नेपाल में अत्यधिक बारिश और अप्रत्याशित जल-प्रवाह के कारण सारण बाढ़ से प्रभावित हुआ। सरयू, गंगा और गंडक नदियों के कारण मकेर, अमनौर, दरियापुर, परसा, सोनपुर, पानापुर, तरैया और रिविलगंज के इलाके प्रभावित हुए। इससे घरों, फसलों, मवेशियों, सड़कों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 7 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। किसानों की फसल

क्षति, क्षतिग्रस्त मकानों और मवेशियों के नुकसान का आकलन कर पात्र लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि क्षति आकलन में पूरे प्रभावित क्षेत्र को शामिल किया जाए। सांसद ने बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य एवं बिजली विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव तथा जल संसाधन मंत्री के साथ लगातार संपर्क में थे। सांसद कंट्रोल रूम के टोल-फ्री नंबर 18003456222 के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं और राहत पहुंचाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कंट्रोल रूम की टीम और मीडिया का आधार बताया। पानी घटने के बाद बीमारियों के खतरे को देखते हुए प्रभावित गांवों में चिकित्सा शिविर लगाने, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले छह माह में क्षतिग्रस्त तटबंधों, सड़कों और पुलों की मरम्मत तथा बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

नामी कंपनी का सौ से अधिक बोरा डुप्लीकेट चावल पकड़ाया, यूपी के राइस मिल के मालिक के शिकायत पर कार्रवाई

अररिया। फारबिसगंज में ब्रांडिंग चावल कंपनी की डुप्लीकेट पैकेजिंग और नामी गिरामी ब्रांडिंग चावल के नाम पर ग्राहकों का आर्थिक शोषण किया जाता है। इसका खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब उत्तरप्रदेश के महाराजगंज जिला के नौतनवा स्थित लक्ष्मी राइस मिल के मालिक नितेश जायसवाल के शिकायत पर फारबिसगंज पुलिस ने छुवापट्टी चौक वार्ड संख्या 16 कादरी मोहल्ला स्थित एक गोदाम में छापेमारी की,जहां एक सौ दस बोरा से अधिक धन लक्ष्मी राइस नाम के ब्रांडिंग वाला डुप्लीकेट चावल के बोरे के साथ बड़े पैमाने पर खाली बोरा पाया गया। यह गोदाम बड़ा शिवालय रोड निवासी कन्हैयालाल जायसवाल का है,जो चावल कारोबारी है। छुवापट्टी में इनका चावल दुकान के साथ बड़े पैमाने पर खुदरा दुकानदारों के साथ अन्य दुकानों में चावल सप्लाई करने का काम करता था।छापेमारी में फारबिसगंज थाना पुलिस के साथ उत्तरप्रदेश के लक्ष्मी राइस मिल के पार्टनर नितेश जायसवाल भी मौजूद थे।

लक्ष्मी राइस मिल के संचालक नितेश जायसवाल ने बताया कि 7 अक्टूबर 2026 को अररिया के पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि फारबिसगंज के छुवापट्टी चौक स्थित मेसर्स गणेश भंडार उनकी कंपनी के रजिस्टर्ड ब्रांड और नाम का रोलत इस्तेमाल कर चावल बेच रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी फर्म कई सालों से चावल बना रही है। गणेश भंडार द्वारा उनके ब्रांड की नकल करने से उनके ब्रांडिंग और व्यापार पर असर पड़ रहा था।श्री



जायसवाल ने बताया कि फारबिसगंज के कई व्यापारियों ने फारबिसगंज सहित अगल बगल के इलाकों में उनके ब्रांडिंग के नाम पर डुप्लीकेसी की शिकायत की थी,जिसको लेकर पूर्व में मेसर्स गणेश भंडार को उन्होंने नोटिस भी किया था।बावजूद उसके द्वारा यह गोरखबंधा लगातार अंजाम दिया जाता रहा। उन्होंने कहा कि उनका फर्म और ब्रांड रजिस्टर्ड है और उसी के फर्म और ब्रांड का इस्तेमाल कर डुप्लीकेट बोरा बनवाकर डुप्लीकेट कम कीमत वाला

चावल विक्री कर मुनाफाखोरी की जा रही थी।उन्होंने बताया कि कन्हैयालाल जायसवाल बगल के गोदाम में चावल का पैकेजिंग करवाता था और इस गोदाम में माल को स्टॉक कर विक्री करने का काम करता था।मामले को लेकर उनके द्वारा लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी गई है। छापेमारी में फारबिसगंज थाना के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार और उपेंद्र यादव समेत अन्य सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे।

सरस मेला ने रचा नया कीर्तिमान, 10 दिनों में 3.83 करोड़ रुपये का कारोबार

पटना,एजेंसी। बिहार में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने की दिशा में जोविका एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभर रही है। जोविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को न केवल रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि उनके पारंपरिक हुनर, स्थानीय उत्पादों और घरेलू उद्यमों को भी व्यापक बाजार उपलब्ध हो रहा है। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 20 से 29 सितंबर तक आयोजित बिहार सरस मेला ने नया कीर्तिमान स्थापित किया।

ग्रामीण विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री ब्रवण कुमार ने शुक्रवार को यहां कहा कि बिहार सरस मेला जैसे आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले उत्पादों को बेहतर विपणन, गुणवत्ता, पैकेजिंग और बाजार संपर्क उपलब्ध कराये जाने से राज्य और देश के व्यापक बाजार में अपनी बेहतर जगह बना रहे हैं। दस दिनों तक चले इस मेले में 3 करोड़ 83 लाख रुपये का कारोबार हुआ, जबकि, साढ़े तीन लाख से अधिक लोगों ने मेले का भ्रमण कर ग्रामीण उत्पादों, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, पारंपरिक व्यंजनों और देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृतिक विविधता का आनंद लिया। बिहार सरस मेला ग्रामीण महिलाओं के हुनर, स्वाद, स्वावलंबन और उद्यमिता का उत्कृष्ट संगम रहा। इस आयोजन ने यह साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा और उद्यमशीलता की

कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल उनके उत्पादों को उचित मंच, बाजार, पहचान और ग्राहकों तक पहुंच उपलब्ध कराने की है। सरस मेला इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दिसम्बर माह में पुनः सरस मेला का आयोजन प्रस्तावित है। पिछले वर्ष आयोजित सरस मेले में लगभग 3 करोड़ 68 लाख रुपये की खरीद-विक्री हुई थी, जबकि इस वर्ष कारोबार बढ़कर 3 करोड़ 83 लाख रुपये पहुंच गया। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 लाख रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि ग्रामीण उत्पादों के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण, महिला उद्यमियों की बेहतर भागीदारी और स्थानीय उत्पादों के लिए विकसित हो रहे बाजार का सकारात्मक संकेत है। बिहार सरस मेला की विशेषता रही कि इसमें बिहार सहित देश के 16 राज्यों की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला उद्यमियों ने भाग लिया। इन महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पाद, हस्तकला, पारंपरिक शिल्प, हस्तकरघा सामग्री, खाद्य पदार्थ और स्थानीय व्यंजन प्रदर्शित किए। अलग-अलग राज्यों की संस्कृतिक पहचान और पारंपरिक कलाओं ने मेले को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए सरस मेला केवल अपने उत्पाद बेचने का अवसर नहीं है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमशीलता को मजबूत करने का मंच भी है। जब ग्रामीण महिला अपने हाथों से तैयार उत्पाद को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाती हैं और उसके हुनर को सम्मान मिलता है, तो इससे उसकी आय बढ़ाने के साथ-साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है।

एक नजर

चीन स्मैश के सेमीफाइनल में हारे मानुष शाह और मानव ठक्कर



बीजिंग,एजेंसी। भारत के मानुष शाह और मानव ठक्कर को शुक्रवार को विश्व टेबल टेनिस स्मैश प्रतियोगिता 2026 के पुरुष युगल सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण कोरिया के लिम जोंगहून और ओह जुनसुंग ने भारतीय जोड़ी को सीधे गेम्ों में 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। शौगांग पार्क में खेले गए मुकाबले में दक्षिण कोरियाई जोड़ी ने 11-8, 11-6, 11-3 से जीत दर्ज की। मुकाबला 20 मिनट से भी कम समय तक चला। भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में अच्छी चुनौती पेश की। मानुष और मानव ने अपनी सर्विस तथा प्रतिद्वंद्वी की सर्विस पर चार-चार अंक हासिल किए, लेकिन इसके बाद दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों ने मुकाबले पर पकड़ मजबूत कर ली। दूसरे गेम में भी भारतीय जोड़ी वापसी नहीं कर सकी। तीसरे गेम में दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और 9-1 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने 11-3 से गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

रणजी ट्रॉफी के लिए सौराष्ट्र की टीम में शामिल हुए रवींद्र जडेजा



राजकोट,एजेंसी। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले मुकाबले के लिए सौराष्ट्र की टीम में शामिल किया गया है। जयदेव उनादकट की कप्तानी में सौराष्ट्र की 16 सर्वस्तीय टीम 11 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। जडेजा हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की एकदिवसीय श्रृंखला में खेले थे, जिसमें भारतीय टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की। जडेजा दो मैचों में केवल दो विकेट ले सके और उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। रणजी ट्रॉफी में खेलने से उन्हें न्यूजीलैंड के आगामी दो टेस्ट मैचों के दौर से पहले लाल गेंद के क्रिकेट में लय हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत को न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन और दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से एक दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में खेलना है। रणजी ट्रॉफी का 92वां संस्करण 11 अक्टूबर से शुरू होगा। पूर्व चैंपियन सौराष्ट्र की एलीट ग्रुप बी में आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब और त्रिपुरा के साथ रखा गया है। सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। उनादकट की कप्तानी में सौराष्ट्र ने 2019-20 और 2022-23 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। टीम ने पिछले सत्र के अपने 14 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। हालांकि, 2025-26 सत्र में सौराष्ट्र की टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। इस बार टीम बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी। उनादकट हाल ही में इंग्लैंड में ससेक्स की ओर से शानदार प्रदर्शन करके लौटे हैं। उन्होंने सात मैचों में 22.21 के औसत से 28 विकेट लिए, जिसमें हैम्पशायर के खिलाफ 32 रन देकर पांच विकेट लेने का प्रदर्शन भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने दो बार एक पारी में चार विकेट हासिल किए। सौराष्ट्र की चयन समिति ने तेज गेंदबाज नील पांड्या और ऑलराउंडर अर्थ यादव को पहली बार टीम में जगह दी है। हार्विक देसाई विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि अर्पित वासवदा, चिराग जानी और जय गोहिल जैसे अनुभवी खिलाड़ी बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। तेज गेंदबाजी की कमान उनादकट के साथ बाएं हाथ के गेंदबाज चेतन सकारिया संभालेंगे। अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर धर्मेद्र सिंह जडेजा अब सौराष्ट्र की जगह छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके जाने के बाद इस सत्र में पार्थ भुत पर स्पिन गेंदबाजी की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी।

सौराष्ट्र की टीम: जयदेव उनादकट (कप्तान), रवींद्र जडेजा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), अर्पित वासवदा, चिराग जानी, प्रेरक मांकड़, जय गोहिल, चेतन सकारिया, अंकुर पंवार, सम्मर गज्जर, पार्थ भुत, विश्वराज सिंह जडेजा, हेतित्वक कोटक, नील पांड्या, अर्थ यादव और तरंग गोहिल।

एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता कुमकुम ने कहा-ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा का स्वर्ण जीतना सपना

नई दिल्ली,एजेंसी। महज 17 साल की उम्र में एशियाई खेलों में इतिहास रचने वाली भारतीय तीरंदाज कुमकुम मोहोद की नजरें अब 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर हैं। महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली कुमकुम ने कहा कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा का स्वर्ण जीतना है। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि इसके लिए उन्हें अपनी तकनीक, शारीरिक मजबूती और मानसिक दृढ़ता पर लगातार काम करना होगा। महााष्ट्र के अमरावती की रहने वाली कुमकुम ने एशियाई खेलों में दो स्वर्ण और एक रजत सहित तीन पदक जीते। उन्होंने महिला व्यक्तिगत रिकर्व के फाइनल में दक्षिण कोरिया की ओह ये-जिन को शूट-ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वह एशियाई खेलों के इतिहास में महिला व्यक्तिगत रिकर्व का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। उन्होंने महिला टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण और मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। कुमकुम ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की ओर से शुक्रवार को आयोजित एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एशियाई खेलों में मिली सफलता से भारतीय तीरंदाजों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ‘दक्षिण कोरिया को हराना भी महत्वपूर्ण था। अब तक व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐसा पदक नहीं आया था। मुझे लगता है कि इस पदक के बाद आने वाली प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन और बेहतर होगा, क्योंकि खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। लॉस एंजिल्स ओलंपिक में जगह बनाने और पदक जीतने के लक्ष्य पर कुमकुम ने कहा कि वह चयन को लेकर अनावश्यक दबाव नहीं लेना चाहतीं।

टी20 में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराया, शाई होप का तूफानी शतक

रांची,एजेंसी। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए टी-20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को छह विकेट से शिकस्त दी है। भारतीय टीम की ओर से दिए गए 250 रनों के विशाल लक्ष्य की वेस्ट इंडीज की टीम ने 19.3 ओवर में ही चार विकेट खोकर (252/4) हासिल कर लिया और तीन गेंद शेष रहते जीत दर्ज कर ली। इस जीत के असली सूत्रधार कप्तान शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड रहे, जिनकी आतिशी बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने पीच पर उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। कामिल पूरन (4 रन) और शिमरॉन हेटमायर (0 रन) सस्ते में पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद कप्तान शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड ने मैदान पर चौकों-छकों की बारिश कर दी। होप ने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 45 गेंदों में 5 चौकों और 9 छकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए। दूसरे ओर से रदरफोर्ड ने अच्छी पारी खेलते हुए सिर्फ 32 गेंदों में 7 चौकों और 7 छकों की बढौलत 94 रनों की तूफानी पारी खेली।

अंत में रोमारियो शेफर्ड ने भी 15 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाकर टीम की ऐतिहासिक जीत पक्की कर दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने संजु सैमसन (82 रन), तिलक वर्मा (नाबाद 44) और ईशान किशन (43 रन) की शानदार पारियों की बढौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज इस बड़े स्कोर का बचाव करने में नाकाम रहे। मयंक यादव (2 विकेट), कुलदीप यादव (1 विकेट) और नमन धीर (1



विकेट) को छोड़कर किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली। अशदीप सिंह, अक्षर पटेल और शिवम दुबे कैरेबियाई बल्लेबाजों के आगे संघर्ष करते दिखे। विशेष रूप से अक्षर पटेल ने अपने 3.3 ओवर के स्पेल में बिना कोई विकेट लिए 63 रन लुटा दिए। वहीं, वेस्टइंडीज की ओर से स्पिनर रोस्टन चेज ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 24

रन देकर 3 विकेट झटकें, जबकि शमार स्प्रिंगर ने 2 सफलताएं हासिल कीं लेकिन वे 4 ओवर में 64 रन लुटा बैठे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शुक्रवार को राची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत एवं वेस्टइंडीज के बीच आयोजित टी 20 क्रिकेट मैच देखने पहुंचे तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

वनडे में 150 विकेट हासिल करने वाली तीसरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बनीं मेगन शट



फीबी लिचफील्ड के हाथों में चली गई। इसके बाद तीसरे ओवर में शट की अंदर की ओर स्विंग होती गेंद शर्मिन सुल्ताना के बल्ले को चकमा देते हुए उनके पैड पर लगी और अपायर ने उन्हें पगबाधा आउट करार दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से शट से पहले एलिस पेरी और कैथरीन फिट्जजैट्रिक ही महिला वनडे क्रिकेट में 150 विकेट का आंकड़ा पार कर सकी थीं। फिट्जजैट्रिक 180 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि पेरी के नाम 166 विकेट हैं। महिला वनडे क्रिकेट में शट कुल मिलाकर 150 विकेट लेने वाली दुनिया की 12वीं खिलाड़ी हैं। इस प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम है, जिन्होंने 255 विकेट हासिल किए हैं। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने चार विकेट लेकर बांग्लादेश की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। एश्ले गार्डनर, उपकप्तान ताहलिया मैक्ग्रा और जॉर्जिया वेयरहैम ने भी एक-एक विकेट लिया। बांग्लादेश की टीम 166 रन पर ऑलआउट हो गई। बांग्लादेश की ओर से रि्तु मोनी ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक 45 रन बनाए। वह टीम की एकमात्र बल्लेबाज रहीं, जिन्होंने 30 से अधिक रन बनाए।

रुस से 0-4 की हार के बावजूद युवा भारतीय टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं कोच क्रिस्पिन छेत्री

कोलकाता,एजेंसी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच क्रिस्पिन छेत्री ने रूस के खिलाफ पहले अंतरराष्ट्रीय मैत्री मुकाबले में 0-4 की हार के बावजूद अपनी युवा टीम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि टीम ने शुरुआती दौर में अच्छा जुझारूपन दिखाया और खिलाड़ियों को इस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

किशोर भारती क्रीड़ांगन में खेले गए मुकाबले में रूस की इयाना शेइना ने 40वें मिनट में शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद स्थानापन्न खिलाड़ी किरा पेतुखोवा ने 60वें और 65वें मिनट में लगातार दो गोल किए। इयाना रिव्स्नुोवा ने 81वें मिनट में गोल कर रूस की जीत 4-0 कर दी। दूसरे हाफ में रूस के लगातार हमलों के सामने भारतीय टीम दबाव में आ गई। मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में छेत्री ने कहा, ‘इस मैच की सकारात्मक बात यह रही कि युवा टीम होने के बावजूद हमने जुझारूपन दिखाया। हम दबाव बनाकर खेलने से नहीं डरते और न ही दौड़ने से घबराते हैं। हम उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं। मुख्य कोच ने टीम के 25 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने रूस की शारीरिक मजबूती और सेट पीस से मिलने वाली चुनौती का सामना करने की



कोशिश की। छेत्री ने कहा, ‘सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जुझारूपन दिखाया और हार नहीं मानी। मेरे लिए यही सबसे अच्छी बात है। छेत्री ने स्वीकार किया कि जून के बाद से प्रतिस्पर्धी हमने खुलासा किया है।

इसके विपरीत रूस की टीम अपनी घरेलू लीग के बीच में है और बेहतर मैच अभ्यास के साथ मैदान पर उतरी थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस मुकाबले से युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव मिलेगा, जो उनके विकास में मददगार होगा। 11 अक्टूबर को होने वाले दूसरे मैत्री मुकाबले को लेकर

छेत्री ने कहा कि टीम का ध्यान लंबे समय तक खेल की तीव्रता बनाए रखने में सुधार करने पर रहेगा। साथ ही, पहले मैच के अंतिम चरण में खेलने वाली युवा खिलाड़ियों को अगले मुकाबले में अधिक अवसर दिए जा सकते हैं। भारतीय टीम का अगला बड़ा लक्ष्य 2029 में होने वाला एएफसी महिला एशियाई कप है। छेत्री ने कहा कि टीम की प्रगति के लिए अधिक खिलाड़ियों का मजबूत समूह तैयार करना महत्वपूर्ण है। रूस के खिलाफ दूसरा मुकाबला युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और पहले मैच से मिली सीख को मैदान पर लागू करने का एक और अवसर देगा।

सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 10 अक्टूबर से झांसी में, 29 टीमें लेंगी हिस्सा

झांसी। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप-2026 10 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के झांसी में शुरू होगी। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में तीन डिवीजन में कुल 29 टीमें हिस्सा लेंगी। डिवीजन ए का फाइनल प्रतियोगिता के अंतिम दिन खेला जाएगा। प्रतियोगिता के 16वें संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी के मुकाबले होंगे। टीमाों को 2025 के संस्करण में उनकी रैंकिंग के आधार पर तीनों डिवीजन में रखा गया है। यह चैंपियनशिप देशभर की टीमों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय स्तर पर खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देगी। पिछले संस्करण में हॉकी पंजाब ने डिवीजन ए के फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर 15वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था। हॉकी उत्तर प्रदेश ने तीसरे स्थान के मुकाबले में मणिपुर हॉकी को 5-1 से हराकर कांस्य स्थान हासिल किया था।

डिवीजन ए में 12 टीमों को चार पूल में बांटा गया है। पूल ए में हॉकी पंजाब, हॉकी यूनित ऑफ तमिलनाडु और हॉकी बंगाल शामिल हैं। पूल बी में हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी महाराष्ट्र और लु पुडुचेरी हॉकी को रखा गया है। पूल सी में हॉकी उत्तर प्रदेश, हॉकी

कर्नाटक और हॉकी चंडीगढ़ हैं, जबकि पूल डी में मणिपुर हॉकी, हॉकी हरियाणा और दिल्ली हॉकी शामिल हैं। डिवीजन ए के मुकाबले 14 अक्टूबर से शुरू होंगे। पूल चरण के बाद 18 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। प्रत्येक पूल की शीर्ष दो टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल 19 अक्टूबर को होंगे, जबकि तीसरे स्थान का मुकाबला और फाइनल 21 अक्टूबर को खेला जाएगा। डिवीजन बी में 10 टीमों दो पूल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। पूल ए में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, असम हॉकी, केरल हॉकी, हॉकी उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हॉकी हैं। पूल बी में हॉकी झारखंड, तेलंगाना हॉकी, गोअस्स हॉकी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव हॉकी तथा हॉकी अरुणाचल शामिल हैं। डिवीजन सी में सात टीमें दो पूल में खेलेंगी। पूल ए में हॉकी मिजोरम, हॉकी हिमाचल और हॉकी जम्मू-कश्मीर हैं। पूल बी में हॉकी आंध्र प्रदेश, हॉकी राजस्थान, बिहार (बीएसएसए) और हॉकी गुजरात को रखा गया है। डिवीजन बी और डिवीजन सी के मुकाबले 10 अक्टूबर से शुरू होंगे। तीनों डिवीजन में टीमें अपने अभियान की मजबूत शुरुआत करने और खिताब की दौड़ में आगे बढ़ने के इरादे से उतरेंगी।

प्रीमियर लीग खिताब के लिए निरंतर बेहतर खेलना होगा, 12वें स्थान पर होना स्वीकार्य नहीं : डियालो



में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए डियालो ने कहा कि नए देश और माहौल में ढलने में उन्हें समय लगा। वह 2021 में प्रीमियर लीग में खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंचे थे। उन्होंने कहा, ‘जब मैं 2021 में इंग्लैंड आया, तो शुरुआती कुछ सप्ताह मेरे लिए अजीब थे। नया देश, नया माहौल, अंग्रेजी नहीं बोल पाना और अलग-अलग संस्कृतियां—मुझे यहां के वातावरण में ढलने में समय लगा। मैंनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ने के बाद मैंने सबसे पहले खुद से कहा, ‘ईश्वर का धन्यवाद!’ यूनाइटेड के लिए खेलना मेरा सपना था। डियालो ने बताया कि क्लब में आने के बाद उनकी मुलाकात अपने आदर्श पॉल पोग्बा से हुई। उन्होंने पोग्बा के साथ तस्वीर खिंचवाने का अनुरोध किया था और बाद में उनके साथ खेलने का अवसर भी मिला। डियालो ने इसे ऐसा अनुभव बताया, जिसे शब्दों

में बयां करना मुश्किल है। डियालो ने 2024 एफए कप के क्वार्टर फाइनल में लिंवरपूल के खिलाफ अतिरिक्त समय में किए गए निर्णायक गोल को अपने करियर के सबसे यादगार पलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि ओल्ड ट्रैफर्ड में अपने प्रशंसकों के सामने बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ निर्णायक गोल करना बेहद भावुक अनुभव था। उन्होंने कहा, ‘एफए कप के क्वार्टर फाइनल में विजयी गोल करना मेरे करियर के बड़े पलों में से एक है। वह भी लिंवरपूल जैसी बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ, ओल्ड ट्रैफर्ड में और अपने प्रशंसकों के सामने। उस समय भावनाएं चरम पर थीं। जश्न मनाने के लिए मैंने अपनी जर्सी उतार दी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कि मुझे पहले ही पीला कार्ड मिल चुका था। इसके बाद मुझे लाल कार्ड मिला, लेकिन मुझे लगता है कि वह अब तक का सबसे अच्छा लाल कार्ड था।’

चोट के कारण भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए मार्क चैपमैन और जैक फॉल्क्स

क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन और ऑलराउंडर जैक फॉल्क्स चोट के कारण भारत के खिलाफ आगामी घरेलू पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर को इसकी पुष्टि की। चैपमैन को पिछले महौने यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग के दौरान बाई जांच की मांसपेशियों में चोट लगी थी। उनके भारत के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज तक फिट होने की उम्मीद है। वहीं, फॉल्क्स को हाल ही में कैंटरबरी में अभ्यास सत्र के दौरान दाएं कुल्हे की मांसपेशियों में चोट लगी। उनकी मैदान पर वापसी की समयसीमा अभी तय नहीं की गई है। न्यूजीलैंड ने टी20 टीम में चैपमैन की जगह ऑलराउंडर जोश क्लार्कसन और फॉल्क्स की जगह तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर को शामिल किया है।

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने दोनों खिलाड़ियों के चोटिल होने पर निराशा जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा, ‘मार्क और जैक के चोटिल होने से मुझे बहुत दुख है। मैं दोनों के जल्द और सहज रूप से स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने आगे कहा, ‘हम भाग्यशाली हैं कि हमें जोश और ब्लेयर के अनुभव का लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। मुझे पता है कि दोनों इस सीरीज में शामिल होने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह एक शानदार टी20 सीरीज होने जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भारत के



खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटरन (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवन जेकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिलने, डैरिल मिचेल, र्लेन फिलिप्स, टिम सीयर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर।

एक नजर

नेपाल में सरकारी शिक्षकों को वाहन खरीदने पर सरकार चुकाएगी 80% किस्तों का ब्याज



काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी शिक्षकों को वाहन खरीदने के लिए ब्याज में राहत देने के प्रावधान सहित शिक्षा (11वां संशोधन) नियमावली को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, माध्यमिक स्तर के प्रथम श्रेणी के शिक्षक 50 लाख नेपाली रुपये तक और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक 40 लाख नेपाली रुपये तक का वाहन खरीद सकेंगे। इसी तरह, माध्यमिक स्तर के तृतीय श्रेणी, निम्न माध्यमिक और प्राथमिक स्तर के सभी श्रेणियों के शिक्षक 4 लाख नेपाली रुपये तक का दोपहिया वाहन खरीद सकेंगे। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि बैंक के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए मिलने वाले वित्तीय ऋण पर लागत राशि के 80 प्रतिशत तक की किस्तों का ब्याज नेपाल सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। शिक्षकों को शेष 20 प्रतिशत राशि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसके बाद वे वाहन खरीद सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षक के सेवा में कार्यरत रहने की अवधि तक संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित किस्तों का ब्याज सरकार वहन करेगी।

न्यूयॉर्क में आईसीई के ऑपरेशन बंद किए जाएं: मेयर ममदानी



न्यूयॉर्क,एजेंसी। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शहर में अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट/आईसीई) के ऑपरेशन को बंद करने की मांग की है। यह मांग ब्रॉक्स में एक आईसीई एजेंट के एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की घटना के बाद की गई। इस घटना के बाद एक अस्पताल के बाहर आईसीई विरोधी प्रदर्शनकारियों और न्यूयॉर्क पुलिस के बीच झड़प हुई है। अस्पताल में घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। मेयर ममदानी ने गुरुवार (स्थानीय समय) को एकस पर लिखा, “आज दोपहर मार्बल हिल के एक रिहायशी इलाके में आईसीई एजेंट ने न्यूयॉर्क के एक निवासी को गोली मार दी। शुरुआती खबरों से पता चलता है कि एजेंटों ने उसकी कार में उसे और एक पांच साल के बच्चे को घेर लिया और फिर कई राउंड गोलियां चलाईं। यह गंभीर स्थिति है। मैंने राष्ट्रपति को फोन किया है। जब हमारी बात होगी, तो मैं मांग करूंगा कि वह हमारे शहर में आईसीई की सभी कार्रवाई बंद करवाएं। मैं चुपचाप यह सब नहीं देख सकता। आज रात हमारी संवेदनाएं घायल न्यूयॉर्क निवासी और उनके परिवार के साथ हैं। हम उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं।”

काठमांडू में 20 किलोग्राम से अधिक सोना बरामद, तीन चीनी नागरिक गिरफ्तार



काठमांडू। नेपाल पुलिस ने काठमांडू के बृह्दानीलकंठ इलाके से 20 किलो से अधिक सोना बरामद किया है। घाटी अपराध अनुसंधान कार्यालय से भेजी गई पुलिस टीम ने विशेष सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। बरामद सोने के साथ तीन चीनी नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, बरामद सोने में 11 किलो सोना तैयार अवस्था में मिला, जबकि 10 किलो से अधिक सोना प्रसंस्करण की तैयारी में रखा गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे सोने की तस्करी में कौन कौन शामिल है। फिलहाल इस तस्करी के सोने सहित गिरफ्तार तीनों चीनी नागरिकों से सघन पृष्ठताछ चल रही है।

ईरान के ‘शैडो फ्लीट’ पर अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए

वाशिंगटन। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए गुरुवार को उसके तेल कारोबार से जुड़े व्यक्तियों, नेटवर्क और 17 जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये जहाज ईरान का कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोकेमिकल्स ले जाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। नये प्रतिबंध अमेरिकी वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ताजा कार्रवाई ईरान के बचे हुए अवैध समुद्री ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है और इससे उसके तेल कारोबार से होने वाली आय पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका ने 14 जुलाई को ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी फिर लागू की थी। यह कदम तेहरान वाशिंगटन के बीच समझौता ज़ापन पर सहमति नहीं बन पाने के बाद उठाया गया था। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, नाकाबंदी से बाहर ईरानी जहाजों पर अब करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल बचा है। इसके मुकाबले दुनिया में रोजाना करीब 10 करोड़ बैरल तेल की खपत होती है।

ओस्लो,एजेंसी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीका की प्रख्यात न्यायविद् नवनीतम 'नवी' पिल्लई को अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने एवं शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नार्वे की राजधानी ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गेन वाट्ने फ्राइडनेस ने उनके नाम का ऐलान किया।

नोबेल समिति के अनुसार, नवी पिल्लई ने युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों और नरसंहार के मामलों में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिल्लई ने असाधारण साहस, सत्यनिष्ठा और नैतिक दृढ़ता के साथ अधिक व्यापक वैश्विक कानूनी व्यवस्था की दिशा में योगदान दिया है। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन सार्वभौमिक कानूनी सिद्धांतों और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। भारतीय तमिल मूल के परिवार में जन्मीं पिल्लई ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला समेत कई लोगों की कानूनी मदद की थी। पिल्लई की जन्म 23 सितंबर, 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। उन्होंने वकालत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और नस्लीय भेदभाव, अलगाव तथा सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ संघर्ष किया। रंगभेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेल्सन मंडेला और अन्य लोगों की पैरवी करने से शुरू हुआ उनका सफर आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक पहुंचा।

पिल्लई दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय, रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायाधिकरण और अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। वह संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं। हाल तक उन्होंने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की अध्यक्षता की। वर्तमान में वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उस मामले की न्यायाधीश हैं,

‘इमरान खान को लॉन्ग मार्च से नहीं मिलेगी राहत’ – आसिफ की चेतावनी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-ईसाफ (पीटीआई) अपने लॉन्ग मार्च के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति जारी रखती है तो उसके नेता इमरान खान को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार दबाव में नहीं झुकेगी। उन्होंने अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पीटीआई पर प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मुल्क की राजधानी इस्लामाबाद के संसद भवन में जियो न्यूज से साक्षात्कार में आसिफ ने कहा कि ‘पीटीआई ने टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है।' उन्होंने कहा कि यह पार्टी की ‘कोरी कल्पना’ है कि वे लॉन्ग मार्च करके सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘सरकार किसी भी हालत में उनसे ब्लैकमेल नहीं होगी।' उन्होंने कहा कि पीटीआई की हर दो-तीन महीने में ‘इस्लामाबाद पर हमला करना’ एक आदत बन गई है। आसिफ ने टीटीपी और उसके अफगान संरक्षकों के बारे में पीटीआई के रुख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अफगान तालिबान नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा, ‘मुझे उनका कोई ऐसा बयान दिखाओ जो टीटीपी या उन्हें सपोर्ट करने वालों के खिलाफ हो। काबुल के शासक नेटा इमरान खान उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवादियों को फंडिंग मिल रही है। वह खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में खुलेआम रह रहे हैं। उन इलाकों में प्रांतीय सरकार का नहीं, आतंकवादियों की तृती बोल रही है। उन्होंने सवाल किया, ‘क्या खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं हैं? रक्षामंत्री ने इस स्थिति को ‘देश और पाकिस्तान के साथ बेईमानी’ का मामला बताया। आसिफ ने पीटीआई से बातचीत की मेज पर आने, घर लौटने और खैबर पख्तूनख्वा के मामलों पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा, ‘बातचीत की मेज पर आएँ और घर लौटें। अपने प्रांत का ध्यान रखें।' साथ ही, उन्होंने पार्टी से आतंकवादियों का समर्थन बंद करने और उनकी फंडिंग रोकने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘यह भूल जाइए कि आप बंदूक के दम पर हमसे अपनी मांगें मनवा पाएंगे।

नेपाल में निलंबित सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक की बर्खास्तगी की सिफारिश

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशी राज दाहाल के खिलाफ जांच समिति ने पद के आचरण के विपरीत गतिविधियों में शामिल होने का निष्कर्ष निकाला है। समिति ने आज गृहमंत्री सुदन गुरुंग को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपते हुए सशस्त्र पुलिस नियमावली के तहत बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की सिफारिश की है। दाहाल पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा का करीबी बताए जाने वाले बिचौलिये इनाम सापकोटा को राज्य से जुड़ी कुछ संवेदनशील सूचनाएं लोक करने का आरोप है। इसी मामले में गृह मंत्रालय ने पिछले सोमवार को उन्हें निलंबित कर जांच शुरू की थी। सशस्त्र पुलिस बल के एआईजी अञ्जनी कुमार पोखरेल की एक सदस्यीय जांच समिति ने गुरुवार को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में दाहाल का बयान भी शामिल है, जिसमें उन्होंने सापकोटा के साथ बातचीत होने की बात स्वीकार की है। सापकोटा फिलहाल काठमांडू परिसर की हिरासत में हैं। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों के बीच हुई बातचीत को भी रिपोर्ट में शामिल किया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, दाहाल के खिलाफ गंभीर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया, ‘किस तरह की कार्रवाई की जाए, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। हालांकि, आचरण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर बर्खास्तगी तक का प्रावधान होने के कारण उसी के अनुरूप कार्रवाई की सिफारिश की गई है। गृह मंत्रालय शुक्रवार को दाहाल से स्पष्टीकरण मांगकर विभागीय कार्रवाई की



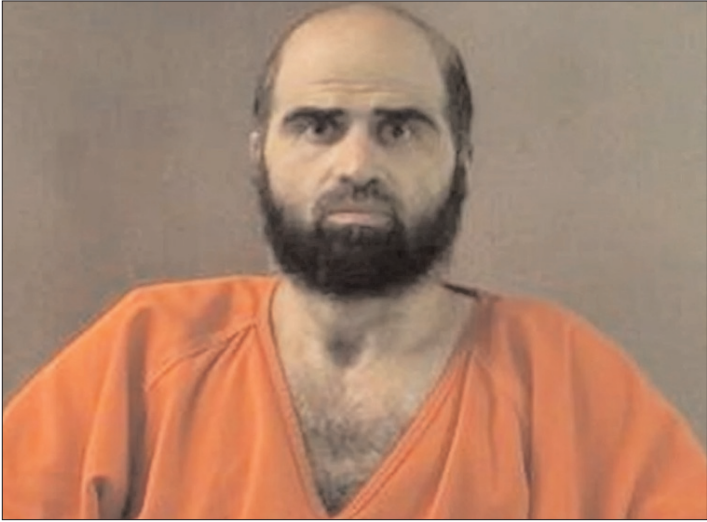
प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। सशस्त्र पुलिस नियमावली के तहत उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाए, इसका अधिकार गृह मंत्री को दिया गया है। 27 सितंबर को काठमांडू क्राइम ब्रांच की पुलिस ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा को हिरासत में लेकर जांच की थी। इसके बाद एआईजी दाहाल ने सापकोटा के माध्यम से राणा को विभिन्न सूचनाएं भेजी थीं। राणा उनके रिश्तेदार हैं। सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि अपने रिश्तेदार की मदद करने के लिए दाहाल ने राज्य के साथ विश्वासघात किया। इसके बाद उन्हें तत्काल निलंबित कर मामले की जांच शुरू की गई। दाहाल के खिलाफ सशस्त्र पुलिस नियमावली के नियम 113 के तहत कार्रवाई होने की संभावना है। इस नियम में सेवा से हटाने और बर्खास्त करने का प्रावधान है। वहीं, नियम 115 के अनुसार, एआईजी को विभागीय सजा देने का अधिकार गृह मंत्री को है। नेपाल के

सशस्त्र पुलिस बल में पहली बार किसी एआईजी के खिलाफ गृह मंत्री के स्तर से विभागीय कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ नेपाल सरकार यानी मंत्रिपरिषद में अपील करने का प्रावधान भी है। एआईजी दाहाल के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय में प्रस्तावित है, जब उनकी सेवा अवधि एक वर्ष बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। सशस्त्र पुलिस बल में एआईजी का कार्यकाल चार वर्ष के साथ एक वर्ष बढ़ाने के प्रावधान के तहत अधिकतम पांच वर्ष तक हो सकता है। दाहाल का चार वर्ष का कार्यकाल 28 असोज को पूरा होने वाला है। सशस्त्र पुलिस मुख्यालय ने उनकी सेवा अवधि एक वर्ष बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजा था। हालांकि, गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सेवा अवधि बढ़ने की संभावना समाप्त हो गई है।

अमेरिका में फोर्ट हुड गोलीकांड के दोषी पूर्व आर्मी मेजर को सबके सामने दी जाएगी मौत की सजा : पीट हेगसेथ

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने गुरुवार को कहा कि आम लोग फायरिंग स्क्वाड के जरिए फोर्ट हुड शूटर मेजर निदाल हसन को दी जाने वाली सजा-ए-मौत को देख सकेंगे, क्योंकि उसे टेक्सास बेस पर सबके सामने सजा दी जाएगी। इसी बेस पर उसने 2009 में 13 लोगों की जान ली थी और 32 लोगों को घायल किया था।

एक्सओस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 90 वर्ष से सजा-ए-मौत को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया है। हेगसेथ के बयानों से यह सवाल उठता है कि सेना लोगों को इसे देखने की इजाजत कैसे देगी। हेगसेथ ने गुरुवार को ‘रियल अमेरिकान वाय्स’ को बताया कि हसन को सैनिकों का एक फायरिंग स्क्वाड 03 दिसंबर को टेक्सास के फिलीन के पास फोर्ट हुड में सजा-ए-मौत देगा। उन्होंने कहा, ‘हम यह पक्का करेंगे कि लोग इसे देख सकें। यह सार्वजनिक हो। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि ऐसी घटना के गंभीर नतीजे होते हैं।' एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन का कहना है कि सजा-ए-मौत की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। पेंटागन ने यह नहीं बताया कि स्ट्रीम को ख़ास तौर पर कहाँ दिखाया जाएगा। रक्षा विभाग ने हेगसेथ के बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। कहा गया है कि 1961 के बाद से यह अमेरिकी सेना द्वारा दी जाने वाली पहली सजा-ए-मौत होगी। फायरिंग स्क्वाड के



जरिए अमेरिकी सेना ने 1945 में सजा-ए-मौत दी थी। अमेरिका में फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजा-ए-मौत का चलन बहुत कम है। डेथ पेनल्टी इनफॉर्मेशन सेंटर के अनुसार, सिर्फ इडाहो, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना और यूटा ही इस तरीके की सजा की इजाजत देते हैं। पिछले साल साउथ कैरोलिना ने राज्य में पहली बार फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजा-ए-मौत दी थी।

यह पिछले 15 वर्ष में अमेरिका में ऐसी पहली घटना थी। अमेरिका में सजा-ए-मौत का आखिरी सार्वजनिक मामला 1936 में हुआ था। तब केंटकी में रेनी बेथिया नाम के एक अश्वेत व्यक्ति को

फांसी दी गई थी। उसे एक श्वेत महिला के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। हेगसेथ ने कहा कि सजा फोर्ट हुड में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हसन ने वहीं जानलेवा गोलीबारी की थी। उन्होंने कहा कि राइफल से लैस सैनिक फायरिंग स्क्वाड बनाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि सजा दोपहर एक बजे होगी, ठीक उसी समय जब हमला हुआ था। अमेरिकी सेना ने एग्जीक्यूशन के लिए तीन दिसंबर 2026 को दोपहर एक बजे (सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम) का समय फोर्ट हुड में तय किया है। सेना के अनुसार, हेगसेथ की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अक्टूबर को मौत की सजा को मंजूरी दी।

एक नजर

निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सीतारमण 9–11 अक्टूबर तक तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सिंगापुर गई हैं। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सीतारमण ने सिंगापुर के राष्ट्रपति से उनके आधिकारिक आवास 'द इस्ताना' में मुलाकात की। इस बैठक में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। वहीं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और जारी ऊर्जा संकट से निपटने के तरीकों पर अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीतारमण ने भारत के घटनाक्रम और निवेश तथा सहयोग के नए अवसरों के बारे में भी जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सीतारमण ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से भी मुलाकात की। बालकृष्णन ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियों के लिए भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं में भागीदारी के कई अवसर हैं। सीतारमण की सिंगापुर यात्रा के सफल रहने की कामना करता हूं। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के दौरान सिंगापुर से भारत में कुल 194.68 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है। जीआईसी और टेमासेक जैसे सिंगापुर के संस्थागत निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा निवेश है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा बैठक अगले साल जनवरी में होगी



नई दिल्ली, एजेंसी। आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा के लिए अगले दौर की बैठक अगले साल जनवरी में भारत में होगी। इसका उद्देश्य वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा करना और बातचीत समय पर पूरी करने के लिए आगे की दिशा तय करना है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ने 6–9 अक्टूबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित आसियान सचिवालय में एआईटीआईजीए की 15वीं संयुक्त समिति की बैठक और इससे संबंधित बैठकों की मेजबानी की थी। इन बैठकों में समझौते की समीक्षा और वार्ता में हुई प्रगति पर विचार किया गया। अब एआईटीआईजीए की संयुक्त समिति की अगली बैठक जनवरी, 2027 में भारत में 'हाइब्रिड' यानी 'ऑफलाइन और' ऑनलाइन' दोनों तरीके से होगी। इसमें उप-समितियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और वार्ता समय पर पूरी करने के लिए आगे के दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। एआईटीआईजीए का यह आयोजन हाइब्रिड फ़ॉरम में हुआ था। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव नितिन कुमार यादव और मलेशिया के निवेश, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की उप महासचिव (व्यापार) सुश्री मस्तुरा अहमद मुस्तफा ने की थी। बैठक में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम सहित आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जकार्ता में हुई बैठक में संयुक्त समिति ने सभी उप-समितियों को समझौते की समीक्षा के तहत लंबित अध्यायों पर काम में तेजी लाने, समय-सीमा के साथ स्पष्ट लक्ष्य तय करने और ठोस प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिए गए थे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने एक अलग समझौते के तहत 'सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ' को सर्वोधिक कर रहे हुए कहा कि स्थापित नियमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि स्थिरता से जुड़े व्यापार उपायों और डिजिटल व्यापार जैसे उभरते मुद्दे वैश्विक व्यापार के एजेंडे को नया रूप दे रहे हैं।

एकदिन पहले की जोरदार गिरावट के बाद शेयर बाजार की शानदार वापसी

नई दिल्ली, एजेंसी। एकदिन पहले गुरुवार की जोरदार गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार आज शानदार वापसी करने में सफल रहा। आज के कारोबार की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद ज्यादातर समय तेजड़िये हावी रहे। हालांकि बीच-बीच में मुनाफा वसूली के चक्कर में मामूली बिकवाली भी होती रही लेकिन बाजार में खरीदारी का जोर इतना अधिक था कि बिकवाली का कोई खास असर शेयर बाजार की चाल पर नहीं पड़ा। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 1.23 प्रतिशत और निफ्टी 1.30 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए।

बीएसई का सेंसेक्स आज 183.43 अंक यानी 0.26 प्रतिशत की मजबूती के साथ 71,776.67 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण इस सूचकांक की चाल में मामूली गिरावट भी आई लेकिन थोड़ी देर बाद ही खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी। शेयरों की लगातार हो रही खरीदारी के कारण आज दोपहर दो बजे के थोड़ी देर बाद यह सूचकांक 1,075.96 अंक यानी 1.50 प्रतिशत उछल कर 22,669.20 अंक के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि आखिरी आधे घंटे के कारोबार में बाजार में हुई मुनाफा वसूली की वजह से सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से 196.87 अंक टूट कर 879.09 अंक यानी 1.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72,472.33 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह एएसईई के निफ्टी ने आज 83.15 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की छलांग लगा कर 22,314.95 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही इस सूचकांक की चाल में मामूली गिरावट भी आई लेकिन इसके

सेंसेक्स और निफ्टी में तूफानी तेजी



बाद खरीदारों ने आक्रामक अंदाज में लिवाली शुरू कर दी। लगातार हो रही खरीदारी के सपोर्ट से निफ्टी 348.95 अंक यानी 1.57 प्रतिशत की छलांग लगा कर 22,580.75 अंक के स्तर पर पहुंच गया। इस स्तर पर पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई। खासकर, आखिरी आधे घंटे के कारोबार में हुई बिकवाली के कारण निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से 60.30 अंक लुढ़क कर 288.65 अंक यानी 1.30 प्रतिशत की मजबूती के साथ 22,520.45 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

आज दिनभर के कारोबार के दौरान आईटी सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी होती रही, जिसके कारण निफ्टी का आईटी इंडेक्स 3.02 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह बीएसई के टेक इंडेक्स ने 2.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया। एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों की भी आज लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का एफएमसीजी इंडेक्स 2.02 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसके अलावा बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गूड्स, कंज्यूमर ड्युरेबल्स, हेल्थकेयर, मेटल और पब्लिक सेक्टर

एंटरप्राइज इंडेक्स भी मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में आज दिन के पहले सत्र में लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। हालांकि दूसरे सत्र में हुई खरीदारी के सपोर्ट से बीएसई का ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। ब्रॉड मार्केट में भी आज लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण निफ्टी का मिडकैप इंडेक्स 1.56 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज दिनभर के कारोबार के दौरान एनएसई में 3,245 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,978 शेयर मुनाफा कम कर हरे निशान में और 1,267 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से सिर्फ एक शेयर बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा, जबकि 29 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं, निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 46 शेयर हरे निशान में और चार शेयर लाल निशान में बंद हुए। आज दिनभर के कारोबार के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से अपोलो हॉस्पिटल 4.72 प्रतिशत, आईटीसी 4.31 प्रतिशत, आयशर मोटर्स 4.17 प्रतिशत, टीसीएस 3.85 प्रतिशत और अदानी पोर्ट्स 3.10 प्रतिशत की मजबूती के साथ आज के टॉप 5 गेनर्स की सूची में शामिल हुए। दूसरी ओर, टॉटेंट पावर 2.14 प्रतिशत, बीएसई लिमिटेड 1.43 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.65 प्रतिशत, जेएसडब्ल्यू स्टील 0.61 प्रतिशत और सिप्ला 0.44 प्रतिशत की कमजोरी के साथ आज के टॉप 5 लूजर्स की सूची में शामिल हुए।

बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि, दोहराई भारतरत्न की मांग– बोलीं, करोड़ों बहुजन ही मेरा परिवार

लखनऊ, एजेंसी।

बहुजन समाज (बसपा) पार्टी के संस्थापक कांशीराम का महापरिनिर्वाण (पुण्यतिथि) पर शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी के सेंट्रल कैम्प कार्यालय 9 माल एवेन्यू के खुले प्रांगण में लगी उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि कांशीराम को देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड 'भारतरत्न' से सम्मानित किया जाए।

मायावती ने कहा कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को भारत के अनुपम संविधान का निर्माता होने के ऐतिहासिक भूमिका सम्मान के बावजूद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लम्बे समय तक उन्हें 'भारतरत्न' की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। अन्ततः बसपा के मजबूत होने पर वीपी सिंह की सरकार में उन्हें 'भारतरत्न' से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि उसी प्रकार कांशीराम को उनके सामाजिक परिवर्तन के ऐतिहासिक योगदान के लिए उन्हें भी 'भारतरत्न' जरूर मिल जाना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिये बसपा की मांग है कि कांशीराम को 'भारतरत्न' से सम्मानित किया जाए।



मायावती ने कहा कि कांशीराम के त्याग, समर्पण आदि की तरह ही, मेरे लिये भी 'बहुजन समाज' के करोड़ों लोग ही मेरे वृहद असली परिवार हैं।

उनका हित, कल्याण, अस्मिता मेरे लिये सर्वोपरि है। देश में 'सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति आन्दोलन को लेकर यही वह भेग आत्मविश्वास, प्रतिज्ञा, शक्ति व ऊर्जा है, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकारों में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए। मायावती ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिज्ञा को मंजिल तक पहुंचाने के लिये सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके 'शोषित वर्ग' को 'शसक वर्ग' बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी कुछ ही माह में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड व पंजाब में होने वाले विधानसभा आमचुनाव में सभी लोगों को और भी अधिक तन, मन, धन की तमयता से लगना है, ताकि कांशीराम जी को सही मायने में उनके

जीवन उद्देश्य के हिसाब से परिपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित हो सके। मायावती ने कहा कि सत्ता प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन, जातिवादी व विषैला है। खासकर ऐसे समय में जबकि संविधान की मानवातावादी व कल्याणकारी पवित्र मंशा को काफ़ी हद तक भूलाकर हर सेवा का विशुद्ध लाभ-हानि के हिसाब से कारोबारी बना दिया गया है, तो फिर लोकतंत्र का चौथे स्तंभ कहलाने वाला मीडिया इससे कैसे अछूता रह सकता है। विरोधियों के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेकों हथकण्डों में अब एकचुअल मीडिया, सोशल मीडिया व एआई भी उनका नया हथियार है, जिसके फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, प्रायोजित न्यूज़ व मिथ्या प्रचार आदि से अति-सावधान रहना है, क्योंकि इनकी नीति बसपा की एकाग्रता एवं ध्यान को आगामी विधानसभा आमचुनाव से भटकाकर सत्ता से दूर रखने का है।

आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में तन मन से जुटे कार्यकर्ता: अखिलेश यादव



देवरिया, एजेंसी। धरती पर जो भी आता है, उसे एक दिन दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन उसके विचार हमेशा जीवित रहते हैं। पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेश यादव के विचार आज भी जीवित हैं। उनके विचारों और संघर्षों को आगे बढ़ाना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह बातें शुक्रवार को लार थाना क्षेत्र के रक्शा गांव में आयोजित पूर्व विधायक सुरेश यादव की श्रद्धांजलि

सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहीं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटने और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बलिया और देवरिया की धरती वीरों और बहादुरों की धरती रही है। यहां के लोगों ने हमेशा संघर्ष,

साहस और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। पूर्व विधायक सुरेश यादव ने भी अपने राजनीतिक जीवन में जनता के बीच रहकर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि उनके विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाना पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। किसी व्यक्ति के जाने से उसका शरीर भले ही समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके विचार समाज को दिशा देते रहते हैं। इसलिए सुरेश यादव के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष ने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि जो अपमानित हो रहा है, वही पीडीए का हिस्सा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज के वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों को साथ लेकर चलने की अपील की। कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है। कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर लोगों से संवाद करें तथा पार्टी की नीतियों और विचारधारा से उन्हें जोड़ें। उन्होंने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव प्रदेश की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। आपसी एकजुटता, मेहनत और जनता के बीच सक्रियता के बल पर ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पीडीए को मजबूत बनाने और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

शारदीय नवरात्र से छठ महापर्व तक फील्ड में उतरें वरिष्ठ अधिकारी, जनता से सीधा संवाद करें : योगी

लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

ने शासन-प्रशासन के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने और उनके समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्र से छठ महापर्व तक वरिष्ठ अधिकारी स्वयं क्षेत्र में उतरें, जनता से सीधा संवाद करें और उसकी समस्याओं के समाधान की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। जनपद स्तर के साथ शासन स्तर पर भी जनशिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा की जाए। दाखिल-खारिज, पैमाइश, वरासत तथा जाति और आय प्रमाणपत्र से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण हो। निर्विवाद राजस्व मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 दिन में किया जाए और प्रत्येक तहसील में लंबित प्रकरणों की सूची सार्वजनिक की जाए। निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

शुक्रवार को शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश का कानून-व्यवस्था, आगामी पर्व-त्योहारों की तैयारियों और जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा, सुगम यातायात और जनसुविधाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीट आरक्षी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता और ईमानदारी से निभाए। करबों और नगरों में यातायात जाम की



स्थिति न बने और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शारदीय नवरात्र से छठ महापर्व तक जोन और रेंज स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक स्वयं क्षेत्र में भ्रमण करें, गश्त में शामिल हों और आमजन से सीधा संवाद स्थापित करें। संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक थाने में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के साथ उन्हें आवश्यक सहायता, परामर्श और विधिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। स्टेंडबाजी करने वालों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाने और एंटी रोमियो स्कॉर्ड की कार्रवाई तेज करने को भी कहा, ताकि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। कोई भी सहकारी समिति खाद के अभाव में स्टॉक विहीन न रहे। जिलाधिकारी स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप खाद

आवंटन के लिए कृषि विभाग को समय से सूचित करें। निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में समुचित व्यवस्था बनाए रखने, पात्र परिवारों को आवास योजनाओं का लाभ दिलाने और सड़क कटिंग से जुड़ी समस्याओं का 31 अक्टूबर तक समाधान करने के निर्देश भी दिए। अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगले 48 घंटे के भीतर वर्षा से हुए नुकसान और राहत वितरण की पूरी जानकारी राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। जिन परिवारों के आवास पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने को कहा। आगामी पर्व-त्योहारों के शांति और सौहार्दपूर्ण आयोजन के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, 18 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी, 19 अक्टूबर को महानवमी और 20 अक्टूबर को विजयादशमी के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुगम आवागमन के पुष्टा इंतजाम किए जाएं।